सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 160, नई दिल्ली । मंगलवार, 20 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 स्कूल के लिए इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और सीपीआर प्रदर्शन पर विशेष सत्र। 06 विदेश व्यापार घाटा कम करना जरूरी 08 मोदी सरकार गिराने की अमरीकी साजिश: रूस

मात्र 110 रुपये में मेरठ से पहुंचे गाजियाबाद, देखो तो बुलेट ट्रेन और बैठो तो प्लेन जैसा एहसास

संजय बाटला

साहिबाबाद और मोदीनगर (उत्तर) के बीच सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब मेरठ साउथ (भूड़बराल) से साहिबाबाद के लिए रविवार (18 अगस्त) से नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इसमें पहली यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना है कि नमो भारत देखने पर तो बुलेट ट्रेन जैसी दिखती और बैठो तो प्लेन जैसा एहसास होता है।

गाजियाबाद। मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक के लिए रविवार यानी 18 अगस्त से नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat Train) की शुरुआत हो चुकी है। यात्रियों ने पहली यात्रा करने का रोमांचक आनंद लिया।

मेरठ साउथ से 160 किमी की गति पकड़ते हुए 29 मिनट में ही ट्रेन 42 किलोमीटर दूर साहिबाबाद पहुंच गई। मेरठ साउथ यानी भूडबराल से जब साहिबाबाद के लिए पहली रैपिड रेल रविवार को निकली तो सबसे ज्यादा खुश बुजुर्ग यात्री नजर आए।

ट्रेन का परिचालन होने से त्योहार पर खर्च की बचत

रक्षाबंधन से एक दिन पहले नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से यात्रियों में खुशी का माहौल दिखा। उनका कहना था कि नमो भारत ट्रेन चलने से न सिर्फ व अब जल्द ही मेरठ तक का सफर कर सकेंगे। बल्कि समय और धन की बचत होगी। ऐसे में उनको त्योहार पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से भी छुटकारा मिलेगा।

मेरठ से साहिबाबाद के बीच आवागमन के लिए मेट्रो की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से पहले बस, ट्रेन ही प्रमुख रूप से सार्वजनिक परिवहन साधन थे।

महंगे किराये से लोगों को मिली राहत

त्योहारों के अवसर पर ट्रेन, बस में सवारियों की संख्या अधिक होने के कारण इन वाहनों में सफर करने के लिए समय अधिक खर्च करना पड़ता था, सार्वजनिक साधन में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण सीट न मिलने पर लोगों को निजी वाहन या प्राइवेट टैक्सी बुक करके आवागमन करना पड़ता है, जिसमें अधिक खर्च होता है।

त्योहारों के अवसर पर दाम भी प्राइवेट टैक्सी चालकों द्वारा अधिक वसूले जाते हैं। अब नमो

भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से इस तरह की समस्या का लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा।

15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी ट्रेन

तेज रफ्तार से चलने वाली नमो भारत ट्रेन सुबह छह बजे से रात दस बजे तक अपने संचालित स्टेशन (साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर नार्थ, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नार्थ, मेरठ साउथ) पर यात्रियों के लिए 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी।

कितने रुपये है किराया?

नमो भारत के मेरठ साउथ स्टेशन से साहिबाबाद स्टेशन तक स्टैंडर्ड कोच में सफर करने पर 110 रुपये और प्रीमियम कोच में सफर करने पर 220 रुपये का किराया लिया जाएगा। नमो भारत का गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के नया बस अड्डा शहीद स्थल स्टेशन से चंद कदम दूर है, ऐसे में यात्री यहां से मेट्रो में बैठकर दिल्ली तक भी आवागमन कर सकते हैं।

क्या बोले लोग?

मैं राजेंद्र नगर स्थित नवीन पार्क में रहती हूं। मुझे रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए मोदीनगर जाना होता है। सार्वजनिक वाहन में भीड़ अधिक होने के कारण निजी कार से मोदीनगर जाती हूं। त्योहार पर जाम की समस्या भी रहती है। ट्रेन का परिचालन शुरू होने से छुटकारा मिलेगा।

– कल्पना सिंह, नवीन पार्क

मेरी बहन मेरठ में रहती हैं, वह रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए गुलधर आती हैं। पिछली बार बस और ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण प्राइवेट टैक्सी बुक करके आना पड़ा था, अब नमो भारत ट्रेन में बैठकर सोमवार को राखी बांधने के लिए गुलधर आएंगी, वहां से थोड़ी दूरी पर ही घर है।

– अभय त्यागी, शाहपुर

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक से कैंटर टकराया, चार की मौत और 24 घायल

दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर कैंटर की बीच सड़क पर खराब खड़े ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में चार लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि कैंटर चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हो गया। घायलों में 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सोमवार की सुबह करीब तीन बजे हुआ।

ग्रेटर नोएडा। दनकौर क्षेत्र स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर सोमवार की सुबह करीब तीन बजे खराब खड़े ट्रक में कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर में सवार 30 लोगों में से चार की मौके पर ही मौत हो गई।

कैंटर में बैंड पार्टी के 30 लोग सवार थे जो हापुड़ से फरीदाबाद की तरफ जा रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनन फानन में क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेस-वे से हटाया गया ताकि कोई और घटना घटित ना हो सके।

पुलिस ने बताया कि मेरठ के तेज गढ़ी चौराहा स्थित शर्मा बैंड पार्टी का हापुड़ में कोई कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बैंड पार्टी के सभी 30 लोग आईसर कैंटर में सवार होकर अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फरीदाबाद के लिए चल दिए। उनकी गाड़ी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर दनकौर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की सुबह करीब तीन बजे पहुंची।

नींद की झपकी आने से हुआ हादसा

बताया जाता है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के किनारे एक टायर फटा ट्रक खड़ा हुआ था। आशंका है कि कैंटर चालक को नींद की झपकी आने के कारण उनकी गाड़ी ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कैंटर में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 24 लोग घायल हो गए जिनमें से 10 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है।

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों द्वारा सूचना दिये जाने के बाद दनकौर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

दिल्ली में बढ़ी रोडरेज की घटनाएं, करोल बाग में स्कूटी टच होने पर सिक्योरिटी गार्ड की हत्या

पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब 12 बजे करोलबाग थाना पुलिस को सूचना मिली कि रैगरपुरा में चाकू से गुदा हुआ एक शख्स खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मनोज को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मनोज एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रोडरेज की घटनाएं बढ़ गई हैं। सड़कों पर चलने वाले लोग वाहनों के टच होने पर झगड़ा करने व एक दूसरे को मारने-मरने पर उतारू हो जाते हैं। ताजा मामला अब करोलबाग में सामने आया है।

शनिवार देर रात करोल बाग के रैगरपुरा में खाना खाने जाने के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड की स्कूटी सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक से टच हो गई। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बात आगे बढ़ने पर युवक ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या ही कर दी।

मरने वाले गार्ड की पहचान 32 वर्षीय मनोज शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को लोक नायक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश में छापेमारी कर रही है।

रैगरपुरा में चाकू से गुदा शख्स सड़क पर पड़ा मिला

पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब 12 बजे करोलबाग थाना पुलिस को सूचना मिली कि रैगरपुरा में चाकू से गुदा हुआ एक शख्स खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मनोज को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि मनोज एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था और रोज देर बीडनपुरा स्थित अपने घर जाता था।

खाना खाने होटल जा रहा था गार्ड

घटना के दौरान वह स्कूटी से खाना खाने रैगरपुरा स्थित एक होटल पर जा रहा था। इस दौरान उसकी स्कूटी ऋषभ नामक युवक से टच हो गई। जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान ऋषभ ने कमर से चाकू निकाल मनोज के सीने पर वार करना शुरू कर दिया। बुरी तरह घायल करने के बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं पाई है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

द्वारका एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी, लोग बोले- काम पूरा होने से पहले ऐसा करना अन्याय है

दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने से लेकर गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक तक द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। इसे दो भागों में (गुरुग्राम एवं दिल्ली भाग) बांटकर निर्माण किया जा रहा है। गुरुग्राम भाग का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि दिल्ली भाग का निर्माण अभी चल रहा है। जिस गति से काम चल रहा है वैसे में दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरा होगा।

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले द्वारका एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स वसूली की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है। एक्सप्रेस-वे के आसपास विकसित सोसायटियों के लोगों ने केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक को पत्र लिखने का निर्णय लिया है।

लोगों का मानना है कि प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले टोल टैक्स वसूलना अन्याय है। यही नहीं, पहले खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाया जाए, फिर द्वारका एक्सप्रेस-वे (प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही) पर टोल प्लाजा चालू किया जाए। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन किया जाएगा।

तेजी से चल रहा टोल प्लाजा बनाने का काम

एक्सप्रेस-वे पर टोल वसूलने के लिए गुरुग्राम-दिल्ली सीमा पर टोल प्लाजा का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। चर्चा है कि टोल प्लाजा का निर्माण पूरा होते ही जितने किलोमीटर तक प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, उतनी दूरी का टोल टैक्स वसूला जाएगा। दो महीने में टोल प्लाजा पूरी तरह तैयार हो जाएगा।

विकसित हो चुकी हैं लगभग 100 सोसायटियां

एक्सप्रेस-वे के आसपास लगभग 100 सोसायटियां अब तक विकसित हो चुकी हैं। कई गांव व कॉलोनियां एक्सप्रेस-वे के आसपास हैं। इनमें लाखों लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यह कहा जा रहा है कि द्वारका एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट पूरा होते ही खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है।

यदि हटाने का विचार होता तो अब तक पचगांव में टोल प्लाजा का निर्माण शुरू हो जाता। पचगांव के नजदीक दिल्ली-जयपुर हाईवे पर टोल प्लाजा बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने जमीन देने पर अपनी सहमति दे चुकी है। उन लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ने की आशंका है।

द्वारका एक्सप्रेस-वे पर टोल वसूली से पहले खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह लाखों लोगों के साथ धोखा है। इस बारे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में मामले से संबंधित एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

पिछले वर्ष ही पूरा होना था प्रोजेक्ट

लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। गुरुग्राम हिस्से का काम एलएंडटी नामक कंपनी लगभग पूरी कर चुकी है। दिल्ली हिस्से की जिम्मेदारी जय कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास है।

भूमिगत बनाया जा रहा चार किलोमीटर भाग

गत वर्ष ही प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन अब इस वर्ष के अंतर्गत पूरा होने की उम्मीद है। एक्सप्रेस-वे का 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में, बाकी 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है। इसमें से 23 किलोमीटर भाग एलिवेटेड और लगभग चार किलोमीटर भूमिगत बनाया जा रहा है।

दिल्ली में पहला भाग गुरुग्राम-दिल्ली सीमा से बिजवासन तक लगभग 4.20 किलोमीटर का है। दूसरा भाग बिजवासन से शिवमूर्ति तक 5.90 किलोमीटर का है। गुरुग्राम इलाके में पहला भाग खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से बसई-धनकोट के नजदीक तक लगभग 8.76 किलोमीटर का है।

दूसरा भाग बसई-धनकोट के नजदीक से गुरुग्राम-दिल्ली सीमा तक लगभग 10.2 किलोमीटर का है। द्वारका एक्सप्रेस-वे से लोग सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे।

4 राशियों पर हमेशा बरसती है हनुमान जी की कृपा, धन से भरी रहती है तिजोरी

वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान हैं। इस राशि में बृहस्पति देव 14 मई 2025 तक रहेंगे। वहीं मंगल देव भी वृषभ राशि में उपस्थित हैं। इस राशि में मंगल देव 25 अगस्त तक रहेंगे। इस दिन मंगल देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषियों की मानें तो हनुमान जी की कृपा 4 राशि के जातकों पर हमेशा रहती है।

मंगलवार का दिन हनुमान जी को अति प्रिय है। इस दिन भगवान श्रीराम संग हनुमान जी की पूजा की जाती है। साथ ही मंगलवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से करियर और कारोबार में जातक को मन मुताबिक सफलता मिलती है। साथ ही जातक अपने जीवन में प्रगति और उन्नति की राह पर अग्रसर रहता है। ज्योतिष भी धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से न केवल व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, बल्कि हनुमान जी की कृपा भी बनी रहती है। ज्योतिषियों की मानें तो 4 राशि के जातकों पर हनुमान जी (Hanuman Ji Favorite zodiac signs) की कृपा हमेशा बरसती रहती है। उनकी कृपा से इन जातकों को हर कार्य में सफलता मिलती है। आइए, इन 4 राशियों के बारे में जानते हैं-

मेष और वृश्चिक राशि

मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं और आराध्य हनुमान जी हैं। इस राशि के जातक गुस्से के तेज होते हैं, लेकिन अदम्य साहस, ऊर्जा से भरपूर और पराक्रमी होते हैं। इन 2 राशि के जातकों के लीडर बनने के योग अधिक रहते हैं। ज्योतिषियों की मानें तो मेष और वृश्चिक राशि के जातक सरकारी क्षेत्र में बेहतर करते हैं। इसके अलावा, कारोबार में भी बेहतर करते हैं। मंगल देव की कृपा से कारोबार में सफलता मिलती है। इसके लिए मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की रुचि बिजनेस करने में होती है। निजी क्षेत्र में दोनों राशि के जातक बेहतर करते हैं। इसके लिए अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। वर्तमान समय मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरस रही है। इसके लिए आय प्राप्ति के नवीन साधन बनेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बिगड़े काम बनेंगे। निवेश के लिए उचित समय है। लाभ प्राप्त होगा। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। धार्मिक यात्रा के योग हैं। खानपान और क्रोध पर नियंत्रण रखें। रोजाना स्नान-ध्यान के बाद हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। वहीं, मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े, मसूर दाल, गुड़, शहद, शिमला मिर्च आदि चीजों का दान करें।

मकर और कुंभ राशि

मकर और कुंभ राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं और आराध्य देवों के देव महादेव हैं। दोनों राशि के जातकों पर साढ़ेसाती चल रही है। मकर राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। वहीं, कुंभ राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। अतः हनुमान जी की कृपा दोनों राशि के जातकों पर बरसती है। उनकी कृपा से मकर और कुंभ राशि के जातकों के सभी बिगड़े काम किसी न किसी माध्यम से बन जाते हैं। धन अभाव होने पर कोई न कोई माध्यम अवश्य बनता है। वहीं, शनिदेव जो न्याय के देवता हैं। उनकी कृपा भी दोनों राशि के जातकों पर रहती है। ज्योतिषियों की मानें तो स्वयं शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि उनके भक्तों को शनि दोष नहीं लगेगा। इसके लिए हनुमान जी की पूजा करने वाले जातकों पर शनिदेव की भी कृपा रहती है। मकर और कुंभ राशि के जातक मंगलवार के दिन पूजा के समय लाल रंग का चोला अर्पित करें। वहीं, शनिवार के दिन पूजा के समय गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है।

मानसून में जन्नत से कम नहीं लगती हैं ये जगहें, पार्टनर संग करें एक्सप्लोर

अगर आप भी प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के शौकीन हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज हम आपको 4 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं।

मॉनसून शुरू होते ही जहां एक ओर मौसम सुहाना हो जाता है, तो वहीं गर्मी से भी राहत मिलती है। अधिकतर लोग मॉनसून में घूमना पसंद करते हैं और इस मौसम में बाहर निकलकर सुंदर नजारों का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के शौकीन हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको 4 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। साथ ही मॉनसून में इन जगहों की खूबसूरती देखने लायक होती है।

शिलांग

अगर आप भारत के किसी ऐसे शहर का दीदार करना चाहते हैं, जहां पर आपको चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव हो। तो आपको शिलांग जाना चाहिए। यहां के नजारे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इस मॉनसून में आप अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर शिलांग जा सकते हैं। जहां पर आप सुंदर फॉल्स और आकर्षक नजारों का दीदार कर सकते हैं।

गोवा

वैसे तो गोवा घूमने का सबसे अच्छा समय ठंड का मौसम होता है। लेकिन अगर आप मॉनसून में गोवा घूमने जाते हैं, तो आपको अद्भुत और अकल्पनीय अनुभव प्राप्त होगा। क्योंकि बारिश के मौसम में गोवा की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में मॉनसून में आपको अद्भुद एक्सपीरियंस होगा।

कुर्ग

कर्नाटक में स्थित कुर्ग एक ऐसा इलाका है, जहां पर आपको कई सारे जंगल देखने को मिलेंगे। इस जगह की सुंदरता बारिश के मौसम में अधिक बढ़ जाती है। यहां पर मॉनसून में आपको कॉफी के बागान और खूबसूरत झीलें आदि देखने को मिलेंगे। वहीं अपने

एक्सपीरियंस को खास बनाने के लिए आप कुर्ग में ट्री हाउस में स्टे कर सकते हैं।

लोनावला

महाराष्ट्र के पास स्थित लोनावला एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। लोनावला के आसपास कई सारे झरने हैं। वहीं यह जगह काफी ऊंचाई पर होने की वजह से आप बादलों की सुंदरता को करीब से देख पाएंगे। मॉनसून में यह जगह स्वर्ग जैसी हो जाती है। यह जगह कपल्स की फेवरेट है और यहां पर कई कपल्स घूमने के लिए आते हैं।

परफेक्ट मेकअप लुक के लिए हर महिला की वैनिटी किट में होनी चाहिए ये 5 चीजें

हर महिला व लड़की को मेकअप करना पसंद होता है। वहीं मेकअप महिलाओं को कॉन्फिडेंट करता है। मेकअप करने पर स्किन नेचुरली चिकनी और मॉइश्चराइज्ड लगती है। लेकिन इसके लिए अच्छी क्वालिटी वाला मेकअप होना चाहिए। जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रख सके। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना सोने से पहले क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराजिंग जरूर करना चाहिए।

वहीं मेकअप के लिए स्किन को तैयार करने के बाद कुछ ऐसे चीजें होती हैं, जो मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाएं रखते हैं।

लैक्मे ल्यूमी फेस क्रीम विद मॉइश्चराइजर

लैक्मे ल्यूमी फेस क्रीम विद मॉइश्चराइजर, हाईलाइटर के साथ आता है। वहीं इसमें हाईऐल्युरोनिक एसिड भी शामिल है। जो आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा इसमें मौजूद नियासिनएमाइड मेकअप को ल्युमिनस फिनिश देने का काम करता है। त्वचा को नरिशमेंट करने के लिए विटामिन सी और विटामिन बी 6 भी होता है।

आयुर्वेदिक क्रीमी मैट माइक्रो मिनी लिपस्टिक

जस्ट हर्ब्स की तरफ से आयुर्वेदिक क्रीमी मैट माइक्रो मिनी लिपस्टिक किट में आपको भारतीय टोन के 16 शेड्स मिलते हैं। इसको एक बार अप्लाई करने पर यह 6 घंटों तक आपके होंठों की खूबसूरती को बनाए रखती है। इसमें आयुर्वेदिक फॉर्मूला शामिल है।

शरीर की चर्बी को कम करने में फायदेमंद है करी पत्ता का जूस, जानिए कैसे करें इसका सेवन

यदि आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो रोजाना नियमित रूप से करी पत्ते के जूस का सेवन करने से मोटापे को कम किया जा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोटापा घटाने के लिए किस तरह से करी पत्ते के जूस का सेवन करना चाहिए।

जिस तरह से खाने में हरा धनिया स्वाद और रंग दोनों को बढ़ाता है। ठीक उसी तरह से करी पत्ता भी खाने का स्वाद बढ़ाता है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। बता दें कि करी पत्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल साउथ इंडियन खाने में किया जाता है। करी पत्ता पोहा और उपमा खुशबू और स्वाद ले आता है। वहीं सदियों से भारतीय घरों में करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। जिससे हमारे शरीर को फायदा मिलता है।

बता दें कि यदि आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो रोजाना नियमित रूप से करी पत्ते के जूस का सेवन करने से मोटापे को कम किया जा सकता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोटापा घटाने के लिए किस तरह से करी पत्ते के जूस का सेवन करना चाहिए और करी पत्ता का जूस कैसे बनाते हैं।

ऐसे बनाएं करी पत्ते का जूस

करी पत्ते का जूस बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी करी पत्ता ले लें। अब इन पत्तों को अच्छे से धो लें और फिर 2 गिलास पानी को उबालने के लिए रख दें। जब तेज आंच पर पानी उबलने लगे, तो इसमें करी पत्ता डाल दें और इसको तब तक उबालें, जब तक यह पानी आधा न रह जाए। फिर पानी को छान लें और इसमें एक चम्मच शहद और नींबू का रस मिक्स कर लें। वहीं आप चाहें तो करी पत्ते को पीसकर भी जूस निकाल सकते हैं और फिर इसमें काला नमक और नींबू डालकर पिएं।

वेट लॉस में फायदेमंद

बता दें कि करी पत्ता एक ऐसा सुपरफूड है, जो तमाम पोषक तत्वों और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। करी पत्ता शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने में सहायक होता है। करी पत्ते में मौजूद तत्व पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। यह बॉडी से विषाक्त पदार्थ को साफ करता है, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है।

इसके साथ ही करी पत्ता में महानिम्बाइन नामक अल्कलॉइड पाया जाता है, जो एंटी-ओबेसिटी प्रभाव होते हैं। ऐसे में इसका सेवन करने से कैलोरी बर्न होती है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है। इसमें विटामिन बी2, विटामिन बी 1 और विटामिन ए जैसे कई विटामिन, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटीडायबिटिक और एंटी-माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है। करी पत्ते में मौजूद सारे पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं।

मसल ग्रोथ के लिए रोजाना खाएं 5 वीगन सुपरफूड्स, सेहत को लेकर नहीं होना पड़ेगा परेशान

अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मीट फिश या अंडे के बिना शरीर को अपनी दैनिक जरूरत के मुताबिक प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो आप गलत हैं क्योंकि यहां हम ऐसे 5 Vegan Superfoods के बारे में बताएंगे जिन्हें डेली डाइट में शामिल कर आप भी सेहत के प्रति बेफिक्र हो सकते हैं। आइए जानें इम्यून सिस्टम को मजबूत करके फायदा पहुंचाने वाले 5 वीगन ऑप्शन्स।

नईदिल्ली। वीगन डाइट फॉलो करने वाले लोग जो मीट, सीफूड या डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं, उनके प्रति एक आम धारणा बन चुकी है कि इस डाइट से उनकी प्रोटीन डेली जरूरत पूरी नहीं हो पाती होगी। प्रोटीन जो कि मांसपेशियों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये शरीर में और भी कई जरूरी काम करता है।

मांसपेशियों के विकास के साथ टिश्यू रिपेयर, जरूरी हार्मोन और एंजाइम का निर्माण और इम्यून सिस्टम के सपोर्ट के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी होता है। इसलिए वीगन हो या नॉन वेजिटेरियन, प्रोटीन हर हाल में शरीर की एक बेसिक जरूरत है। कई लोगों को लगता है कि नॉन वेजिटेरियन तो मीट, फिश, अंडे आदि से प्रोटीन की भरपूर आपूर्ति कर लेते हैं, लेकिन वीगन लोगों के लिए प्रोटीन के विकल्प सीमित हो जाते हैं, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। वीगन डाइट फॉलो करने वालों के पास भी प्रोटीन के ढेरों विकल्प हैं जो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड हैं।

मसल ग्रोथ के लिए खाएं ये 5 वीगन सुपरफूड

टोफू

टोफू के एक कप (250 ग्राम) में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। टोफू वीगन डाइट फॉलो करने वालों का पनीर माना जाता है। टोफू करी, सलाद, क्रिस्पी बेक्ड टोफू या टोफू सैंडविच जैसी कई क्रिएटिव और टेस्टी डिशेज टोफू से तैयार की जा सकती हैं। ये प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होने के साथ बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है।

दाल

हर 100 ग्राम दाल में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। इसमें शरीर के लिए जरूरी लगभग सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम के भी बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं। वैसे भी एक भारतीय थाली बिना दाल के पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए हर प्रकार की दाल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।

पीनट बटर

हर 100 ग्राम पीनट बटर में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ये बटर डायबिटिक्स के लिए भी फायदेमंद है और साथ ही बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रोटीन का एक जबरदस्त विकल्प है।

पंपकिन सीड्स

हर 100 ग्राम पंपकिन सीड्स में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ ये जिंक और एंटी ऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं जो मसल ग्रोथ के साथ एंजाइटी और डिप्रेशन से भी राहत दिलाता है।

स्पिरुलिना

हर 100 ग्राम स्पिरुलिना में लगभग 57 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है जो कि इसे एक बेहद बेहतरीन प्रोटीन रिच फूड ऑप्शन बनाता है। असल में ये एक ब्लू एल्गी होता है जो प्रोटीन रिच होने के साथ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है।

इन राशि के जातकों को धारण करना चाहिए माणिक रत्न, मान-सम्मान में होगी वृद्धि

माणिक रत्न को धारण करने से जातक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे में हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने जा रहे हैं कि किस राशि के जातकों को माणिक रत्न धारण करना चाहिए।

ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को विशेष महत्व बताया गया है और सभी रत्नों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। अगर व्यक्ति अपनी राशि के हिसाब के रत्न धारण करते हैं, तो उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है और परेशानियों का अंत होता है। बता दें कि माणिक रत्न को धारण करने से जातक के सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे में हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने जा रहे हैं कि किस राशि के जातकों को माणिक रत्न धारण करना चाहिए।

मेष राशि

मेष राशि के जातक माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। मेष राशि का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। वहीं माणिक भी सूर्य का रत्न माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिसके फलस्वरूप इस राशि के जातकों को कई लाभ मिल सकते हैं। इस रत्न को धारण करने से जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। माणिक रत्न को धारण करने से मेष राशि के जातकों को ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है।

सिंह राशि

माणिक रत्न धारण करना सिंह राशि वालों के लिए शुभ माना जाता है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह भी सूर्य होता है और माणिक सूर्य का रत्न माना जाता है। सिंह राशि के जातकों द्वारा इस रत्न को धारण करने से उनके मान-सम्मान में वृद्धि होती है और साहस व पराक्रम बढ़ता है। इसके अलावा रोग-दोष से छुटकारा मिलता है और कुंडली में स्थित ग्रह बाधाओं को दूर करने के लिए सिंह राशि के जातकों को माणिक रत्न धारण करना चाहिए। इस राशि के जातकों को रविवार के दिन सोने या तांबे की अंगूठी में माणिक रत्न को धारण करना चाहिए।

धनु राशि

इस राशि के जातकों के लिए भी माणिक रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। गुरु और सूर्य ग्रह धनु राशि के मित्र ग्रह हैं। ऐसे में इस रत्न को धारण करने से जातक के ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है और सुख-समृद्धि के साथ भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है। हालांकि धनु राशि के जातक माणिक रत्न पहनने से पहले पूजा-पाठ और शुद्धिकरण अवश्य करवा लें। तभी इस रत्न को धारण करने से लाभ मिल सकता है।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह रत्न धारण करना शुभ फलदायी माना जाता है। चंद्रमा और सूर्य ग्रह कर्क राशि के मित्र माने जाते हैं। ऐसे में इस रत्न को धारण करने से कर्क राशि के जातकों को मानसिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। वहीं यदि कुंडली में ग्रह दोष हैं, तो उससे भी छुटकारा मिलता है। वहीं यदि आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी है, तो माणिक रत्न को धारण करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है।

दिल्ली में 2014 के बाद बने लाखों मकानों पर तोड़फोड़ का खतरा, 17 साल में हुए अवैध निर्माण का डाटा जुटा रही एमसीडी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद दिल्ली के लाखों मकानों पर तोड़फोड़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली नगर निगम जून 2014 के बाद यानी 17 साल में हुए अवैध निर्माण और कार्रवाई का डाटा जुटा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में कम से कम ऐसी 10 लाख संपत्ति हैं जिनका निर्माण जून 2014 के बाद हुआ है।

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद एक ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनीटरिंग कमेटी की सक्रियता नजर आने लगी है तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद राजधानी में जून 2014 से अनधिकृत कॉलोनियों में हुए अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ का खतरा मंडराने लगा है।

दरअसल, हाईकोर्ट ने न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी में अवैध निर्माण पर सुनवाई करते हुए निगम से अब तक दिल्ली में अवैध निर्माण और उस पर कार्रवाई का जो विवरण मांगा था, उससे निगम द्वारा एकत्रित किए जा रहे आंकड़ों से बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की जानकारी सामने आ सकती है। फाइलों में धूंल फांक रहे अवैध निर्माणों की सूची जल्द ही हाईकोर्ट में होगी। इस पर आने वाले समय में कोर्ट निर्णय कर सकता है।

अनधिकृत कॉलोनियों में हुआ अवैध निर्माण

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में अवैध निर्माण को संरक्षण देने के लिए दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट है। इसके तहत नियमित कॉलोनी में अवैध निर्माण आठ फरवरी 2007 तक संरक्षण प्राप्त हैं, जबकि ग्रामीण और अनधिकृत कॉलोनियों में अवैध निर्माण को एक जून 2014 तक संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद जो-जो अवैध निर्माण हुए हैं वह कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी एक आदेश मिला है। इसमें हाई कोर्ट के आदेश पर निगम के इंजीनियरिंग विभाग ने सभी 12 जोन के अधिशासी अभियंताओं (भवन) जोन अनुसार आठ फरवरी 2007 से लेकर पांच अगस्त 2024 तक अवैध निर्माण और उन पर कार्रवाई से लेकर संपत्ति के मालिक की जानकारी के साथ वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है।

दिल्ली में फिर सीलिंग और तोड़फोड़ का दौर लौटने की आहट, कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं लाखों संपत्तियां

करीब 10 लाख हैं ऐसी संपत्तियां

19 अगस्त तक सभी जोन को निगम मुख्यालय को यह जानकारी देनी है। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में कम से कम ऐसी 10 लाख संपत्ति हैं जो अवैध रूप से निर्मित हैं और उनका निर्माण खासतौर पर ग्रामीण और अनधिकृत कॉलोनियों में जून 2014 के बाद हुआ है। दिल्ली में शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगांई ने कहा कि निगम जब इन संपत्तियों की लिस्ट लेकर जाएगा तो संभव है कि हाईकोर्ट कार्रवाई रिपोर्ट मांग ले।

DDA की तीनों नई आवासीय योजनाओं के ब्रोशर आज से उपलब्ध, फ्लैटों का पंजीकरण 22 अगस्त से; जानें बुकिंग राशि

डीडीए के द्वारका में बने एमआईजी एचआईजी व सुपर एचआईजी फ्लैटों के लिए 21 अगस्त सुबह 11 बजे से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसी समय अवधि से लोग फ्लैटों की बयाना राशि को ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। ई-नीलामी में हिस्सा लेने और बयाना राशि ऑनलाइन जमा करने के लिए 16 सितंबर शाम छह बजे तक समय निर्धारित किया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सस्ता घर, मध्यम वर्गीय एवं द्वारका विशेष... तीनों नई आवासीय योजनाओं के ब्रोशर सोमवार से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इन्हें डीडीए के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके बाद 39,400 फ्लैटों के लिए पंजीकरण 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा। खरीदार अपनी प्राथमिकता अनुसार सैंपल फ्लैटों को देख सकेंगे। डीडीए के द्वारका में बने एमआईजी, एचआईजी व सुपर एचआईजी फ्लैटों के लिए 21 अगस्त सुबह 11 बजे से पंजीकरण शुरू होगा। इसी समय अवधि से लोग फ्लैटों की बयाना राशि को ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। ई-नीलामी में हिस्सा लेने और बयाना राशि आनलाइन जमा करने के लिए 16 सितंबर शाम छह बजे तक समय निर्धारित किया गया है। फ्लैटों के अनुसार ई-नीलामी की प्रक्रिया को ऑनलाइन तोड पर ही 24 से 26 सितंबर के दौरान शुरू किया जाएगा। इसी तरह सस्ता घर और मध्यम वर्गीय योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और अन्य फ्लैटों के लिए बुकिंग प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। इन दोनों आवासीय योजना को डीडीए 31 मार्च 2025 को समाप्त करेगा। खास बात यह है कि सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड और शिफ्ट होने के लिए एकदम तैयार बताए जा रहे हैं। मालूम हो कि तीनों ही योजनाओं में शामिल फ्लैटों के लिए पंजीकरण शुल्क 2500-2500 रुपये निर्धारित किया गया है। सस्ता घर योजना में फ्लैटों की कीमत में 15 प्रतिशत की छूट शामिल है और सामान्य आवास योजना के तहत नरेला के कुछ सेक्टरों में बने फ्लैटों पर सरकारी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।

कोरोनाकाल के बाद इस साल अगस्त में सबसे साफ हवा में सांस ले रही दिल्ली, बीते 22 दिन से 100 से नीचे है AQI

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कोरोना काल (2020) के बाद इस साल अगस्त में दिल्लीवासी सबसे ज्यादा साफ हवा में सांस ले रहे हैं। रविवार यानी 18 तारीख तक एक भी दिन यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) नहीं बिगड़ा। एक तारीख से ही यह लगातार 100 से नीचे यानी 'संतोषजनक' श्रेणी में है।

वैसे यह स्थिति 28 जुलाई से ही बनी हुई। मतलब, 22 दिन से दिल्ली की हवा एकदम साफ चल रही है। इससे पहले वर्ष 2021 के सितंबर में लगातार 20 दिन एक्यूआई 100 से नीचे रहा था। पिछले वर्ष साफ हवा की सबसे लंबी अवधि 13 दिनों की रही थी।

वर्षा के असर से हवा रहती है साफ-सुथरी

अमूमन राजधानी में प्रदूषक कण पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर सामान्य से ज्यादा रहता है। लेकिन, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में वर्षा के असर से हवा सबसे ज्यादा साफ-सुथरी रहती है। इस बार राजधानी में मध्यम और भारी वर्षा तो कम हुई है लेकिन लगभग दिल्ली में कहीं न कहीं हल्की वर्षा हर दिन ही हो रही है। इसके कारण हवा में घुले-मिले प्रदूषक कण काफी हद तक साफ हो गए हैं।

आठ अगस्त को रही थी सबसे साफ हवा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एक्यूआई) के आंकड़े बताते हैं कि आठ अगस्त को वायु गुणवत्ता सबसे बेहतर रही थी। इस दिन एक्यूआई सिर्फ 53 दर्ज किया गया था।

2020 से 2024 तक अगस्त में कितने दिन 100 से नीचे रहा AQI

2020- 31 दिन
2021- 11 दिन
2022- 18 दिन
2023- 08 दिन
2024 (18 तारीख तक)- 18 दिन

साफ हवा की सबसे लंबी अवधि

वर्ष 2024 - 28 जुलाई से 17 अगस्त तक (21 दिन)
वर्ष 2023 - 05 जुलाई से 17 जुलाई तक (13 दिन)
वर्ष 2022 - 23 जुलाई से 02 अगस्त तक - (11 दिन)
वर्ष 2021 - 07 सितंबर से 26 सितंबर तक (20 दिन)

दिल्ली सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सीएजी की 11 रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखे : देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने सीएजी की 11 रिपोर्ट को विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर विधानसभा पटल में रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के मुख्यमंत्री केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष को लगातार दिल्ली सरकार के विभागों के लेखा जोखा की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पत्राचार को वित्त मंत्री आतिशी द्वारा सिरे खारिज करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक मान्यताओं का अपमान करना है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार का बही खाता वर्तमान 11 सीएजी रिपोर्ट और 2022 से लंबित रिपोर्ट पर भाजपा एक-दो दिन बोलकर चुप्पी साधने का मतलब यह तो नही कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में भाजपा भी केजरीवाल के साथ बराबर की भागीदार है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब जेल से बाहर थे तब हर मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करते थे परंतु सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में रखने को लेकर न विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई जवाब आया है और न ही जेल में बैठे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का, और वित्त मंत्री आतिशी सीएजी रिपोर्ट को दबाकर आम आदमी पार्टी की साख को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि सीएजी की राज्य वित्त, प्रदूषण निवारण, दिल्ली में शराब का विनियमन और आपूर्ति, विनियोग खाते, सार्वजनिक उपक्रमों और सामाजिक व सामान क्षेत्रों से संबधित तथा देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर निष्पादन लेखा परीक्षा से संबधित रिपोर्ट शामिल है और इनमें से कुछ रिपोर्ट 2022 से लंबित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री का दायित्व है कि वो सरकार के काम काज की रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे।

उन्होने कहा कि आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ने अब पीठासीन बनने की कवायद तेज कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मामले में वो अपना विधानसभा क्षेत्र दूसरी विधानसभाओं पदयात्रा कर रहे जिससे केजरीवाल नाखुश दिखाई देते है। एक के बाद एक नए मामले आम आदमी पार्टी में आने के बाद जेल से केजरीवाल अपनो मनाने में विफल साबित हो रहे है। 15 अगस्त झंडा सलामी का मामले के बाद आतिशी नाखुश है, वे सिसोदिया की पदयात्रा से नदारद है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल हो या उनके मंत्रीमंडल के मंत्री या दिल्ली नगर निगम में सत्तासीन मेयर कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल रहे है। जल संकट, सीवर ओवर फ्लां, बिजली, स्वच्छ पेयजल, सफाई व्यवस्था, गाद निकालने का काम कुछ भी हो सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर दोष मंडकर अपना पल्ला झाड़ने के महारथी है। उन्हांने कहा कि थोड़ा बारिश थमने पर दिल्ली में बदहाल सफाई व्यवस्था पर दिल्ली की मेयर जिनका काम ही दिल्ली की सफाई व्यवस्था दुरस्त रखना है, वो निगमायुक्त को पत्र लिखकर उन्हें सफाई ओर कूड़े के ढेरों भरी दिल्ली से अवगत करा रही है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की प्रशासनिक असफलता और लगातार ध्वस्त होते दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली की जनता को सबक लेना चाहिए।

मेरठ में पत्रकारों की महा तिरंगा विशाल रैली हुई संपन्न

सुषमा रानी

दिल्ली। ठाकुर ओमपाल सिंह ऑल इंडिया मीडिया क्लब की विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए राज्य प्राप्त दर्ज मंत्री एडवोकेट धर्म सिंह अपने संबोधन में पत्रकारों को चौथे स्तंभ का सिपाही बताते हुए उनसे भारत को शिक्षित और नशा मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉ० एम० क्यू० मलिक चेयरमैन ऑल इंडिया मीडिया क्लब रजिस्टर्ड द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर चलने और पूर्ण सहयोग देने की बात कही।

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ऑल इंडिया मीडिया क्लब द्वारा द्वितीय विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें मेरठ शहर के तमाम पत्रकार साथियों ने बढ़चढकर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एडवोकेट धर्म सिंह रहे जिनका स्वागत ऑल इंडिया मीडिया क्लब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल सिंह ठाकुर व उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने फूल माला पहनाई और मेरठ मंडल संरक्षक मनोज निर्मल व मेरठ मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा, सचिव राजीव कुमार ने पगड़ी पहनाई और जिला मेरठ संरक्षक नरेंद्र शर्मा ने पटका पहनाया और जिला मेरठ अध्यक्ष हिमा गौड़ कोशिक व मेरठ महानगर अध्यक्ष सनि कश्यप व वंशिका शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्य मंत्री धर्म सिंह ने अपने संबोधन में ऑल इंडिया मीडिया क्लब द्वारा किए जा रहे हैं इस कार्य की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि मीडिया दुनिया का चौथा स्तंभ है इसको अपनी पूरी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए क्योंकि मीडिया दुनिया को आईना दिखाने का काम करती है मीडिया जैसा दुनिया को दिखाती है दुनिया वैसा ही देखते हैं राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में नशा मुक्ति व शिक्षा पर भी जोर दिया और उपस्थित सभी लोगों को नशे की लत को छोड़ने व दुसरो का भी नशा छुड़वाने का संकल्प दिलाकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ऑल इंडिया मीडिया क्लब के सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हुए देश के सभी पत्रकारों के उज्जवल भविष्य की कामना की और जमकर भारत माता की जय जयकरो का उद्घोष किया तत्पश्चात राज्य मंत्री एडवोकेट धर्म सिंह ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। यह तिरंगा यात्रा सर्किट हाउस से शुरू होकर कचहरी अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब को माल्यार्पण कर कमिश्नरी चौराहे से होते हुए जीरोमाइल चौराहा, बेगमपुल चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहे पर महाराणा प्रताप को माल्यार्पण कर इविज चौराहे से इंदिरा चौक व सूरजकुंड रोड होते हुए वापस सर्किट हाउस पर सम्पन्न हुई। ऑल इंडिया मीडिया क्लब द्वारा निकल गई इस तिरंगा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में सिविल लाइन थाने से एस.आई. अमित कुमार, हे.कां. मनोज कुमार, हे.कां. अमित कुमार, हे.कां. राहुल कुमार, और ट्रैफिक पुलिस से यशवीर सिंह व उनके हमरहा का विशेष योगदान रहा। इस तिरंगा यात्रा के समापन से पूर्व उपस्थित सभी लोगों ने जलपान भी किया तत्पश्चात ऑल इंडिया मीडिया क्लब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल सिंह ठाकुर व शैलेंद्र सिंह ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर ऑल इंडिया मीडिया क्लब के जिला मेरठ अध्यक्ष हिमा गौड़ कौशिक, जिला मेरठ संरक्षक नरेंद्र शर्मा, मेरठ महानगर अध्यक्ष शनि कश्यप, मेरठ महानगर संरक्षक ध्रुव सिंह, प्रदेश सदस्य गौरव पांचाल, मेरठ सदस्य रिचर्डसन सिंह, जायद खान, वंशिका शर्मा, अंश ठाकुर, एम.एस. उपाध्याय, नईम शैफी, नौशाद, एस.आर.अली, सिकंदर, संजय चौधरी, नावेद खान, रविंद्र कुमार, गौरव पांचाल, नंदराम सिंह, मोहित, दिलशाद मन्नू भाई, शुभम पाल, रोहित पाल आदि पत्रकार साथी मौजूद रहे।

रिश्तों को "मोल" दो

क्या? तुम्हारी नज़र में
रिश्तों की क़द्र,
यहीं रह गई बाकी.
साथी का मिला साथ,
बाकी सभी रह गए
तुमसे खाली हाथ.
कब ये समझ पाओगे,
कि अभिभावकों को
तुम्हारे ही कारण,
नज़रे झुकाना पड़ती होंगी.
उन्हें भी रिश्तों के
टूटने का मलाल,
होता ही होगा.
अभी-भी संभल जाओ,
अति हुई नहीं हैं,
मति से काम लो कि
क्षति हुई नहीं हैं.
देखों डोर हाथ में है,
परिवार भी साथ में हैं.
रह जाए ना कसक,
परे रखो अकड़ व ठसक.
बस, लबों को खोल दो,
थाम लो सबका हाथ,
रिश्तों को "मोल" दो.

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्य प्रदेश)
98260 25986

स्कूल के लिए इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और सीपीआर प्रदर्शन पर विशेष सत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली ब्रिगेड ने गवर्नमेंटः बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोलड़ बंद न्यू दिल्ली 110044 में, 17 अगस्त 2024 को। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और सीपीआर प्रदर्शन पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया सत्र का उद्देश्य नागरिकों व युवाओं में जागरूकता पैदा करना और विकास करना है हृदय और श्वसन संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के बारे में युवाओं और बच्चों के बीच समझ। यह इसमें सुरक्षा निर्देश, पहचान और चरण-दर-चरण कार्रवाइयां, और सीपीआर का प्रदर्शन शामिल था (हृदय व फेफड़ो को पुनर्जीवन देना)। कोविड-19 के बाद, कई लोगों को लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया है गंभीर हृदयाघात, विशेषकर युवा लोगों में।

इस सत्र में स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य सहित छह शिक्षकों और 220 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया शिक्षक और प्रबंधन समिति के सदस्य छात्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए उपस्थित रहकर कल्याण भी करें। सत्र दोपहर 2:00 बजे से आयोजित किया गया जोकि शाम 5.30 बजे तक जारी रहा लगभग तीन घंटे तक. सत्र के अंत में, प्रतिभागियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया प्रभावी सीपीआर परिणामों के लिए सही तकनीकों के साथ डमी पर अभ्यास करें। प्रतिभागियों ने अभ्यास भी किया किसी हताहत को संभालने और स्थानांतरित करने का कौशल। यह सत्र उत्साहपूर्ण बातचीत के साथ संपन्न हुआ और छात्रों और शिक्षकों की प्रतिक्रियाएँ।

श्री पी ड़ी वर्खिया सहायक आयुक्त के नेतृत्व में दक्षिण-पूर्व और दक्षिण जिले की दिल्ली ब्रिगेड टीम। सुश्री मोनिका, कोर अधिकारी (नर्सिंग), और श्री श्याम, कोर अधिकारी, ने आयोजन किया सत्र का संचालन किया, और स्कूल प्रशासन की ओर से श्री उमा शंकर गुप्ता जी व श्री सुरेश मिश्रा जी ने स्कुल स्तर पर ब्रिगेड टीम से समन्वय किया। विद्यालय अधिकारियों ने सत्र की सराहना की और इसे अधिक स्कूलों तक विस्तारित करना चाहा क्योंकि यह मूल्यवान प्रदान करता है जीवन बचाने वाला ज्ञान. दिल्ली ब्रिगेड इस जागरूकता को सभी शैक्षणिक लोगों तक फैलाने के लिए समर्पित है जीएनसीटी दिल्ली में संस्थान, क्योंकि यह आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

रक्षाबंधन के मद्देनजर बस अड्डों, मेट्रो स्टेशन और बाजारों में चेकिंग, संदिग्धों की ली गई तलाशी

डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद का कहना है कि रक्षा बंधन पर सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान अगर कोई महिला अपने भाई को पति बहन स्वजन या अन्य रिश्तेदारों के साथ दोपहिया पर पीछे बैठकर भाई को राखी बांधने के लिए जा रही होगी तो उसे वाहन चेकिंग के नाम परेशान नहीं किया जाएगा।

नोएडा। रक्षाबंधन से पहले नोएडा शहर में पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की गई। पुलिस ने यह अभियान मुख्यतः भीड़भाड़ वाले इलाकों, बस अड्डों, मेट्रो स्टेशन, शापिंग माल और बाजारों के आसपास चलाया, ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोका जा सके।

पुलिस का यह प्रयास त्योहार के दौरान शहर में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया। एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्र का कहना है कि रक्षाबंधन से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत प्रमुख मार्गों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, मेट्रो स्टेशन, शापिंग माल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों और लोगों की गहन जांच की। अभियान का उद्देश्य त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और शहर में सुरक्षा का माहौल बनाए रखना था।

संदिग्धों पर रखी जा रही नजर

इस दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर खास नजर रखी गई। पुलिस ने कई जगह पर वाहनों के दस्तावेज, हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन की जांच की। अभियान में कई लोगों के वाहनों का चालान भी किया गया और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। अभियान शहरवासियों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया, ताकि वह त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मना सकें।

हेलमेट पहनना भूली बहनों का चालान नहीं करेगी पुलिस

डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद का कहना है कि रक्षा बंधन पर सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान अगर कोई महिला अपने भाई को पति, बहन, स्वजन या अन्य रिश्तेदारों के साथ दोपहिया पर पीछे बैठकर भाई को राखी बांधने के लिए जा रही होगी तो उसे वाहन चेकिंग के नाम परेशान नहीं किया जाएगा।

ऐसी महिलाओं को हेलमेट पहनने की सलाह दी जाएगी। हालांकि चालान की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उन्हें हेलमेट पहनने के फायदे गिनाए जा सके। हालांकि दोपहिया चला रहे चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस ने रक्षाबंधन पर महिलाओं का नहीं किया चालान, बहनों को पहनाया हेलमेट

नोएडा में रक्षाबंधन पर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनूठी पहल की। सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों और बस अड्डों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। दोपहिया सवार महिलाओं को रोककर वाहन का चालान करने के बजाए उन्हें हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। रक्षाबंधन पर उपहार में हेलमेट पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे।

नोएडा। रक्षाबंधन पर सोमवार को नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक अनूठी पहल की। सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों और बस अड्डों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। दोपहिया सवार महिलाओं को रोककर वाहन का चालान करने के बजाए उन्हें हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। ट्रैफिक पुलिस से रक्षा बंधन पर उपहार में हेलमेट पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे।

उन्होंने ट्रैफिक पुलिस का धन्यवाद कर भविष्य में दोपहिया से यात्रा के दौरान हेलमेट पहने का भरोसा दिया। पहल की लोगों ने सराहना की करके एक सकारात्मक कदम बताया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान भविष्य में भी चलाए जाएंगे जिससे सड़क पर होने वाले हादसों में कमी लाई जा सके।

बहनों को उपहार देते हुए नो चालान-डे मनाया

डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद का कहना है कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर रक्षा बंधन पर सभी बहनों को उपहार देते हुए नो चालान-डे मनाया। जिले के 11 चौराहों पर रक्षा बंधन के दिन अभियान चलाकर एक हजार से अधिक महिलाओं को हेलमेट वितरित किए गए। सेक्टर-37, सेक्टर-62, परी चौक सहित अन्य चौराहों पर अभियान चलाया गया।

राखी बांधने के लिए जा रही महिलाओं को हेलमेट वितरित

अभियान के दौरान पति, बहन, स्वजन, रिश्तेदारों के साथ दोपहिया पर पीछे बैठकर भाई को राखी बांधने के लिए जा रही महिलाओं का चालान करने के बजाए उन्हें हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी। स्वयं स्कूटी चलाकर भाईयों को राखी बांधने के लिए जा रही महिलाओं को भी हेलमेट वितरित किए गए। सभी बहनों को समझाया गया कि सड़क दुर्घटनाओं से जीवन रक्षा हेतु हेलमेट अवश्य पहने।

अपने भाई व परिवार के सदस्यों को भी बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाने दे। जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे। रक्षा बंधन के दिन जिन दोपहिया वाहनों में महिलाएं सवार रहीं। उन वाहनों के चालान नहीं किए गए। उनको यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। किसी भी महिला को वाहन चेकिंग के नाम परेशान नहीं किया गया। उन्हें हेलमेट पहनने के फायदे गिनाए जा सके।

नोएडा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित होगा डायट, रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डायट बनने के बाद शिक्षकों छात्रों और डायट प्रशिक्षुओं को एक छत के नीचे अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नई शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत ही डायट प्राचार्य को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (आइआइएम) लखनऊ में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने और प्रबंधन की बारीकियां सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को 15 करोड़ रुपये से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 23 अगस्त को डायट प्राचार्य लखनऊ में आयोजित बैठक में शामिल होंगे।

दूसरे चरण में करीब छह डायट को चुना जाना है, जिसमें गौतमबुद्ध नगर भी शामिल हो सकता है। पहले चरण में 70 में से 13 डायट को चुना गया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डायट को चुने जाने के बाद यहां अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डायट बनने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान इंफार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी (आइसीटी) लैब का प्रयोग कर सकेंगे। इससे छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा। पुस्तकालय के साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

15 करोड़ रुपये से विकसित होगा डायट

डायट में अत्याधुनिक कक्षाएं व प्रयोगशालाएं, डिजिटल पुस्तकालय और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट शासन की ओर से मिलेगा।

वर्तमान में डायट में बड़ा प्रशिक्षण कक्ष नहीं होने से जिले के शिक्षक एक साथ प्रशिक्षण लेने से वंचित हो जाते हैं, जबकि डायट परिसर में जगह की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही छात्रों के पाठ्यचर्या ढांचे, पाठ्य-पुस्तकों में परिवर्तन और शिक्षण सामग्री को उन्नत बनाने के लिए डायट प्रवक्ता कार्य करेंगे।

इन 13 जिलों में बनाए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

पहले चरण में प्रदेश के 70 में 13 जिलों के डायट सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, उनमें वाराणसी, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, इटावा, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर व मुजफ्फरनगर शामिल हैं।

गुरुग्राम में प्लॉट बेचने के नाम पर व्यापारी से चार करोड़ की धोखाधड़ी,

गुरुग्राम में प्लॉट बेचने के नाम पर व्यापारी से चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने व्यापारी को गांव सिकंदरपुर घोषी में नौ वर्ग गज प्लॉट के फर्जी कागज दिखाए थे। पीड़ित को जब पता चला कि आरोपितों ने दो साल पहले ही किसी दूसरे को प्लॉट बेच दिया था। इससे उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई।

गुरुग्राम। सेक्टर 15 पार्ट दो निवासी एक व्यापारी से प्लॉट बेचने के नाम पर चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर रविवार को दस लोगों के विरुद्ध शिवाजी नगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

इसमें कहा कि कुछ लोगों ने उसे प्लॉट बेचने के नाम पर चार करोड़ रुपये ले लिए। जबकि वह प्लॉट पहले ही किसी और को बेचा जा चुका था। सेक्टर 15 पार्ट दो निवासी मनोज कुमार लांबा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका शक्ति नगर में प्लास्टिक दाना सप्लाई करने का काम है।

उनकी फर्म जिले के कई कंपनियों को माल सप्लाई करती है। संदीप यादव और मनोज यादव की मानेसर में ऑटो पार्ट और प्लास्टिक बनाने की कंपनी है। मनोज लांबा ने कहा कि माल सप्लाई को लेकर उनकी संदीप और मनोज यादव से पिछले पांच साल से अच्छी जान-पहचान थी।

सस्ते दामों में प्लॉट देने का दिया झांसा

दोनों लोग फरवरी 2021 में उनकी फर्म में आए। कहा कि गांव सिकंदरपुर घोषी में नौ सौ वर्ग गज प्लॉट करीब साढ़े सात करोड़ रुपये में मिल रहा है। उन्होंने अपने पास पैसे न होने का हवाला देकर मनोज लांबा से सस्ते दामों में प्लॉट लेने की पेशकश की।

आरोप है कि मनोज लांबा के राजी होने पर मार्च में दोनों लोगों ने हल्का पटवारी से प्लॉट के कागज भी दिखवाए। इसके बाद मनोज लांबा ने संदीप और मनोज यादव के कहने पर कथित रूप से अर्श डेवलपर्स से प्लॉट की सात करोड़ 30 लाख रुपये में डील की।

अक्टूबर 2021 में तय हुई रजिस्ट्री की बात

मनोज यादव के कहने पर मनोज लांबा ने अप्रैल 2021 में इकरारनामा के रूप में डेढ़ करोड़ रुपये नकद और 50 लाख रुपये बैंक खाते में जमा कराए। नकदी शक्ति नगर स्थित फर्म के ऑफिस में दोनों आरोपितों को दी गई। अक्टूबर 2021 में रजिस्ट्री की बात तय हुई।

इससे पहले जून 2021 में संदीप और मनोज यादव समेत पांच लोग उनके ऑफिस में एक बार फिर आए। उन्होंने दो करोड़ और नकद रुपये मांगे। कहा कि वह जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री करा देंगे। ये रुपये भी दे दिए गए।

प्लॉट देखने गए तो उड़े होश

मनोज लांबा ने आरोप लगाया कि जब वह अक्टूबर 2021 में सिकंदरपुर घोषी स्थित प्लॉट देखने गए तो यहां पर एसकेएन हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी प्लॉट पर निर्माण करा रही थी। पूछताछ करने पर पता चला कि यह प्लॉट एजेंसी ने 2019 में ही अर्श डेवलपर्स से खरीदा था।

धोखाधड़ी का पता चलने पर जब मनोज लांबा ने संदीप और मनोज यादव से पूछा और रुपये वापस करने के लिए कहा तो उन्होंने बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी।

देश में महिला उत्पीड़न दोष कानूनों में नहीं, उन्हें लागू करने वाले सिस्टम में

परिवहन विशेष

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि हमारे देश में महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन लगातार जारी है। जब तक कोई इतनी गंभीर और जघन्य हिंसक घटना न हो जाए जिसमें किसी पीड़ति की मौत या वह बुरी तरह घायल न हो जाए तब तक लोगों का ध्यान उस घटना की ओर नहीं जाता।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि हमारे देश में महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन लगातार जारी है। जब तक कोई इतनी गंभीर और जघन्य हिंसक घटना न हो जाए जिसमें किसी पीड़ति की मौत या वह बुरी तरह घायल न हो जाए तब तक लोगों का ध्यान उस घटना की ओर नहीं जाता। एक बात यह भी है कि इस तरह की अमानवीय घटनाओं के मामले में राजनीतिक फायदे के लिए आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। आरोपियों को बचाने के लिए किसी तरह से मामला लटकाने की कोशिश की जाती है। इस का परिणाम यह होता है कि सबूत गायब हो जाते हैं और मामले कमजोर पड़ जाते हैं।

आखिर हमारे समाज में हिंसा की इतनी अधिक भावना आई कहां से? क्यों ऐसा है कि एक छोटी बच्ची से लेकर बड़ी आयु की महिला तक के साथ इस प्रकार की दरिंदगी की जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारा समाज पितृ प्रधान बन गया है। इसमें पुरुष जो चाहते हैं वही होता है। कामकाजी महिलाओं के बारे में हमारे समाज में यही समझा जाता है कि वे 2-4 वर्ष काम करने के बाद शादी करके घर पर बैठ जाएंगी। एक बंधी-बंधाई विचारधारा सी बन गई है जिसमें हमारा समाज महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं देना चाहता। वास्तव में महिलाओं का शोषण घर से ही शुरू होता है। पढ़ाई-लिखाई, अधिक स्वतंत्रता तो दूर की बात है अपने शरीर, समय और विरासत पर भी कोई अधिकार समाज उसे नहीं देना चाहता।

इस तरह के हालात में उचित रूप से यह पूछा जा सकता है कि इस समय कोलकाता के सरकारी कालेज में बलात्कार की शिकार डाक्टर युवती के पक्ष में प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिलाओं के साथ ममता बनर्जी प्रदर्शन क्यों कर रही हैं। सरकार भी उनकी, पुलिस भी उनकी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। प्रश्न यह भी है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में पुलिस क्यों हमेशा लाचार हो जाती है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद सबूत मिटाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ हमला करने आ गई और उसे रोकने के लिए पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया। यदि पुलिस वाले कम थे तो क्या वे फोन करके और सहायता नहीं मंगवा सकते थे? हर बार जब भी बलात्कार का कोई केस होता है, तो उसकी थोड़ी-बहुत चर्चा मीडिया में आती है परंतु अंत में मीडिया वाले तथा अन्य सभी चले जाते हैं और केवल न्याय के लिए तरस रही पीड़ति तथा उसके परिवार वाले ही अकेले रह जाते हैं।

उलटे पीड़ति पर ही सवाल उठाए जाते हैं कि वह देर से घर से निकली होगी, परिधान ठीक नहीं पहने होंगे, वह अमुक जगह क्यों सो रही थी, जैसा कि कोलकाता के अस्पताल बलात्कार कांड में हुआ है। जहां कालेज प्रबंधन ने महिला डाक्टरों के रहने के लिए कमरा नहीं बनवाया था, जबकि पुरुष डाक्टरों के लिए यह व्यवस्था थी। यहां तक कि महिला डाक्टरों के लिए बाथरूम तक नहीं था। यदि सुविधाएं ही नहीं होंगी, तो महिला सुरक्षा सम्बन्धी कानून कैसे लागू किए जा सकेंगे? पश्चिम बंगाल की सरकार यह कह रही है कि दोषी को फांसी दे दो परंतु जब तक दोषी को यह संदेश नहीं जाएगा कि बलात्कार करके वह बच नहीं सकता और हर हालत में सजा मिल कर ही रहेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पुलिस और वकीलों में पुरुषों की बहुसंख्या होती है वहां उन्हीं के दृष्टिकोण से फैसले होते हैं। भारत में प्रति घंटे बलात्कार के 4 केस होते हैं जबकि केस केवल 30 प्रतिशत मामलों में ही चलते हैं। ऐसे हालात में लोग महिलाओं को सम्मान देना कहां से सीख पाएंगे?

कामकाजी तथा अन्य महिलाओं के मामले में हमारे कानून पहले भी अच्छे थे तथा नए कानूनों को और भी कठोर बना दिया गया है परंतु उन्हें लागू करने के लिए उसी तरह के लोगों की भी जरूरत है। जैसा कि कोलकाता बलात्कार और हत्या केस में सामने आया है जहां मामले को शुरू से ही दबाने की कोशिश की जा रही थी। कालेज के प्रिंसीपल का दूसरी संस्था में तबादला कर दिया गया है। जब तक प्रबंधन किसी घटना के प्रति जवाबदेह नहीं होगा तब तक ऐसे कदमों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। थोड़ा प्रोटैस्ट तो होगा परंतु एक महीने के बाद सब शांत हो जाएगा। जैसा कि हाल ही के दिनों में मणिपुर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं के उत्पीडन के मामले में हमने देखा है। निष्कर्ष रूप में तो यही कहा जा सकता है कि हमारा सिस्टम ही सबूत नष्टां करके, मामले को दबा कर या लटका कर वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश करता है क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है जिसमें हम महिलाओं को समानता का अधिकार देना नहीं चाहते।

गलत इंजेक्शन से युवती की मौत का आरोप, इंसाफ के लिए निकाला कैंडल मार्च

गुरुग्राम में एक युवती की अस्पताल में गलत इंजेक्शन से मौत को लेकर परिवार के लोगों ने इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला। साथ ही अस्पताल और डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस आयुक्त को अस्पताल पर कार्रवाई के लिए शिकायत दी गई। लेकिन डेढ़ साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

गुरुग्राम। न्यू कॉलोनी के नेहरू लेन निवासी एक युवती की अस्पताल में गलत इंजेक्शन से मौत होने के बाद कहीं सुनवाई न होने पर परिवार के लोगों ने इंसाफ के लिए शाम को कैंडल मार्च निकाला। परिवार ने अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सौरभ छाबड़ा ने बताया कि उनकी 22 वर्षीय बहन सिमरन की 21 जनवरी 2023 को खांसी जुकाम से तबीयत खराब थी। इसलिए वह ज्योति पार्क स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर के कहने पर नर्स ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन रिएक्शन करने से थोड़ी देर में ही सिमरन की मौत हो गई।

अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई

परिवार ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद न्यू कॉलोनी, एसीपी, डीसीपी और पुलिस आयुक्त तक को अस्पताल पर कार्रवाई के लिए शिकायत दी गई। डेढ़ साल बाद अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

परिवार के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सिमरन को इंसाफ दिलाने के लिए मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे। कैंडल मार्च लेडी फातिमा से शुरू होकर मदनपुरी रोड से गीता भवन मंदिर, दशहरा ग्राउंड से होकर न्यू कॉलोनी पुलिस थाना पहुंचा। यहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया।

गला दबाकर महिला की हत्या, बोरे में बांधकर फेंका शव

सेक्टर 53 थाना क्षेत्र के वजीराबाद में मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर के पास खाली प्लाट में बोरे में बंद महिला का शव बरामद किया गया। महिला की गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। शरीर पर चोटों के निशान नहीं हैं। पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार सेक्टर 53 के वजीराबाद ढाणी में मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर के गार्ड ने कंट्रोल रूम में रविवार दोपहर दो बजे संदिग्ध बोरा पड़े होने की जानकारी दी थी। इसके बाद थाना पुलिस, एफएसएल और सीन आफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची। बोरे में महिला का शव बरामद किया गया। इसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई गई। टीमों ने साक्ष्य एकत्रित कर शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है।

शव पर अन्य कहीं भी चोटों के निशान नहीं हैं। वहीं अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई। सेक्टर 53 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र ने बताया कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच कर यह पता लगा रही है कि यहां बोरा किसने फेंका। वहीं शव की पहचान करने के लिए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

नगर परिषद ने ई-रिक्शाओं पर नंबर लगाना भूली, 3 हजार में से 1 हजार का ही नंबर लगाया, रूट चार्ट भी नहीं बना

परिवहन विशेष न्यूज

किशनगंज में ई-रिक्शा परिचालन और इससे होने वाली जाम की समस्या पर नियंत्रण के प्रति नगर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। शहर में तीन हजार से अधिक ई-रिक्शा संचालित हैं। इनमें से एक तिहाई ई-रिक्शा बंगाल से आते हैं। शहर में एक भी पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण ई-रिक्शा चौराहों पर खड़े होकर यात्रियों का इंतजार करते हैं। इससे रोजाना जाम की स्थिति बनती है। इसे नियंत्रित करने के लिए नगर प्रशासन की ओर से मास्टर प्लान बनाया गया था। लेकिन यह अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया।

नगर परिषद को शहर में चलने वाले सभी ई-रिक्शा को नंबर देना था और उनका रूट चार्ट निर्धारित करना था। ई-रिक्शा की नंबरिंग भी शुरू कर दी गई। करीब तीन दिनों तक नगर निगम कर्मियों ने टाउन हॉल के सामने कैंप लगाकर नंबरिंग का काम किया। जिसमें करीब एक हजार ई-रिक्शा की नंबरिंग की गई। इसके बाद नगर परिषद शेष ई-रिक्शा की नंबरिंग करना भूल गई। न तो ई-रिक्शा की नंबरिंग का काम पूरा हुआ और न ही रूट चार्ट निर्धारित हो सका।

12 साल में ई-रिक्शा बन गए यातायात व्यवस्था के लिए नासूर, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, ताकि दिल्ली में लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। इसके लिए दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न अपराधों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना लगाना, अपंजीकृत ई-रिक्शा को जब्त करना और ओवरलोड भारी माल वाहनों को निशाना बनाना शामिल है।

दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 05 से 17 अगस्त तक 13 दिनों की अवधि के दौरान 674 ई-रिक्शा और 121 भारी मालवाहक वाहन जैसे ट्रक, ओवरलोडिंग के लिए जब्त किए गए। इसके साथ ही 291 मध्यम और हल्के वाहन भी जब्त किए गए।

आजकल सड़कों पर ई-रिक्शा की अधिक संख्या के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको लेकर प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रही है। ई-रिक्शा के मामले में प्रशासन ने पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों तरह के ई-रिक्शा को जब्त कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि अगर पंजीकृत ई-रिक्शा भी नियमों का पालन नहीं करते हैं और उन सड़कों पर चलते हैं जहां उन्हें प्रतिबंधित किया गया है तो कार्रवाई की जाती है।

ई-रिक्शा को चलते हुए तकरीबन 12 साल हो गए है। यह साल 2012 में चलने शुरू हुए थे और बहुत जल्द ही ये पूरे शहर में फैल गए। नियमों का पालन न करने की वजह से ये एक बड़ी समस्या बन गए हैं। अधिकारी के मुताबिक सड़क पर ई-रिक्शा की वजह से होने वाली समस्याओं में ट्रैफिक जाम और लंबी कतारें, गलत पार्किंग, प्रतिबंधों का उल्लंघन, वन-वे उल्लंघन, यात्रियों को ओवरलोड करना और कम उम्र में गाड़ी चलाना शामिल हैं।

जीरो कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक ने बाजार में मचाई सनसनी

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता जीरो मोटरसाइकिल ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी करके भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस साझेदारी के तहत जीरो मोटरसाइकिल भारत में अपने प्रमुख मॉडल जीरो एफएक्सई को लॉन्च करने की योजना बना रही है। जिसे हाल ही में बेंगलुरू में परीक्षण के दौरान देखा गया। जीरो एफएक्सई को 'केए-01' टेस्ट नंबर प्लेट के साथ बेंगलुरु में परीक्षण के दौरान देखा गया। यह एक शक्तिशाली स्ट्रीट बाइक है जिसमें शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन राइडिंग रेंज है। इस बाइक की अधिकतम गति 136 किमी प्रति घंटा है और इसे एक बार चार्ज करने पर 170 किमी तक चलाया जा सकता है। इसमें 7.2kWh का बैटरी पैक है, जो इसे लंबी दूरी तक चलने की क्षमता देता है।

एफएक्सई अपने बेहतरीन डिजाइन और प्रीमियम पोजिशनिंग के लिए जानी जाती है। अमेरिका में इसकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, जो इसे दुनिया के सबसे महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक बनाती है। हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार के लिए इसका सस्ता वेरिएंट लॉन्च करेगी। जिसमें कुछ फीचर्स कम किए जा सकते हैं ताकि कीमत को और आकर्षक व किफायती लग्जरी बनाया जा सके।

हीरो मोटोकॉर्प की जीरो बाइक के पूर्ण उत्पादन में जाने की योजना भारतीय बाजार में किफायती कीमत पर लोडेड जीरो ईवी को देखने की काफी गुंजाइश दिखाती है। इस बाइक के बारे में जानकारी तब सामने आई है जब 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक ने भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इस लिहाज से अल्ट्रावॉयलेट एफ77, ओबेन रोअर, कोमाकी रेंजर, टॉर्क क्रेटोस जैसे मौजूदा मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा तेज होगी, जिससे बाजार में विभिन्न विकल्पों के साथ प्रतिस्पर्धी बाजार का और विस्तार होगा।

मध्य प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी में दोपहिया से लेकर बस खरीदी पर मिलेगी नकद सब्सिडी

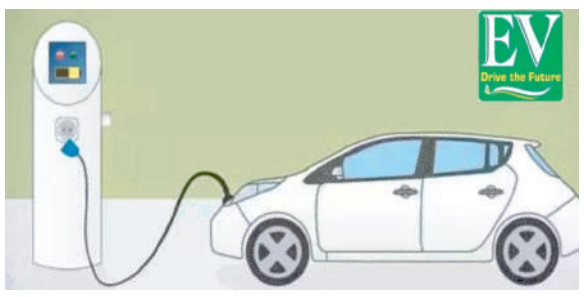

परिवहन विशेष न्यूज

मध्य प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी में दोपहिया से लेकर बस खरीदी पर मिलेगी नकद सब्सिडीमध्य प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार इंसेटिव देगी। यह इंसेटिव 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग पाइंट लगाना अनिवार्य होगा। सरकारी कार्यालयों में भी चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। एक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर चार्जिंग प्वाइंट का उपयोग किया जा सकेगा।नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश की पांच वर्षीय नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर लिया है और शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। इसे स्वीकृति मिलते ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और सस्ता हो जाएगा।अभी इलेक्ट्रिक वाहन पर एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगता है, जिसे सरकार शून्य करने पर विचार रही है यानी अब नए इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर आरटीओ में वाहन पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि यह व्यवस्था एक निश्चित समय और सीमित संख्या के वाहनों के लिए ही होगी।इसके अलावा ईवी वाहनों की पार्किंग भी फ्री करने का प्रस्ताव है। बता दें कि 2019 में बनी ईवी पालिसी को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने नई पालिसी के लिए केंद्र सरकार की पालिसी का अध्ययन कराया है और इसी के अनुरूप नई पालिसी तैयार की गई है।इलेक्ट्रिक आटो रिक्शा के लिए शहरों में रूट तय होंगे। नगर निगम और निकाय स्तर पर इनके रूट किलोमीटर के हिसाब से तय किए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत शहरों में शापिंग माल और आफिस की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से पार्किंग आरक्षित की जाएगी। पार्किंग स्थान पर चार्जिंग प्वाइंट भी होंगे।दिन में चार्ज के शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि रात्रि में चार्ज करने पर बिजली का 100 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। सरकारी वाहनों की खरीद में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक साइकिल, दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन, बस एवं माल वाहक वाहनों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी।इन वाहनों की श्रेणियों के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे ऋण पर ब्याज में छूट, परमिट, पंजीयन एवं रोड टैक्स में छूट के साथ ही वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन के साथ बैट्री स्वैपिंग के लिए 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।इसमें परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया गया, ताकि क्रियान्वयन में परेशानी न आए। ईवी के लिए सिंगल विडो क्लीयरेंस स्थापित करने की भी योजना है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर) बना रही है।नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने का प्रविधान किया जा रहा है। वाहन के पंजीयन से दस साल तक टोल टैक्स से छूट दी जाएगी। शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 552 ई-बसें भी खरीदी जाएगी।

मुजफ्फरपुर में ई-रिक्शा के लिए लागू होगी कलर कोड योजना

परिवहन विशेष न्यूज

मुजफ्फरपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में जाम की समस्या को कम करने के लिए सरकार ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई योजना के तहत हर रूट को अलग-अलग रंग दिया जाएगा, ताकि रूट ओवरलैपिंग की समस्या को कम किया जा सके और ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। इस योजना की शुरुआत राज्य परिवहन मुख्यालय ने की है, जिसमें डीटीओ, एडीटीओ, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।

इस कलर कोड योजना के तहत शहर को अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा और हर जोन के लिए एक खास रंग तय किया जाएगा। ऑटो और ई-रिक्शा संचालक अपने वाहनों को उसी रंग में रंगेंगे जो उनके रूट के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में वाहनों की संख्या को भी नियंत्रित किया जाएगा। हर रूट में यात्रियों की संख्या का आकलन करके वाहनों की संख्या तय की जाएगी, ताकि वाहनों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक जोन में पंजीकृत वाहनों पर उसी जोन के पुलिस थाने का टैग लगाया जाएगा तथा संचालन लाइसेंस वाले अधिकृत सेवा प्रदाताओं के लिए कलर कोड का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें डीएम, एसपी, डीएसपी, डीटीओ, जिले के सिविल सर्जन तथा संबंधित यूनियनों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

इस योजना के सफल कार्यान्वयन से शहर में यातायात की स्थिति में सुधार की उम्मीद है, जिससे जाम से निजात मिलेगी और वाहन चालकों एवं यात्रियों दोनों को लाभ होगा।

मैपमाईइंडिया के नोटिस पर भाविश अग्रवाल ने कहा, 'खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं'

नई दिल्ली। हाल ही में मैपमायइंडिया ने ओला मैप पर चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। कंपनी ने कहा कि ओला मैप्स बनाने के लिए मैपमायइंडिया का डेटा चुराया गया। कंपनी के सीईओ बार-बार ओला पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कंपनी के इवेंट 'संकल्प' के दौरान प्रेस ब्रीफिंग में इसका जवाब दिया है। भाविश अग्रवाल ने मैपमायइंडिया के दावों को अवसरवादी बताया है। उन्होंने कहा- 'खाली बर्तन बहुत शोर मचाते है। हमारे आईपीओ के दौरान उन्होंने बहुत शोर मचाया था। वे इस मामले में पूरी तरह अवसरवादी हैं। हम आईपीओ के बाद उनसे निपटना चाहते थे, हमने उन्हें कड़ा जवाब भेजा है। अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक पर हमला किया, जो मैपिंग बिजनेस का हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया वह अवसर मिलने जैसा है। हम उनसे सही जगह और सही समय पर बात करेंगे।' मैपमाईइंडिया की पैरेंट कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स ने ओला पर आरोप लगाया है कि उसने मैपमाईइंडिया के डेटा का इस्तेमाल ओला मैप्स बनाने के लिए किया है। आरोप है कि कंपनी ने मैपमाईइंडिया के डेटा को कैश करके सेव कर लिया है और लाइसेंस प्राप्त उत्पाद के डेटा की नकल कर ली है। उस समय भी ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा था कि सीई इंफो सिस्टम्स द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से झूठे और भ्रामक हैं। मैपमाईइंडिया की पैरेंट कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स ने ओला इलेक्ट्रिक को कानूनी नोटिस भेजकर ओला मैप्स पर कंपनी का डेटा कॉपी करने का आरोप लगाया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने लाइसेंसिंग समझौते का उल्लंघन किया है, जिस पर 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। ओला इलेक्ट्रिक ने एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए मैपमाईइंडिया के साथ साझेदारी की थी।

ई-रिक्शा मामले में कार्रवाई को सरकार ने लिया समय

परिवहन विशेष न्यूज

ई-रिक्शा के संचालन को लेकर कार्रवाई के लिए शासन ने हाईकोर्ट से समय लिया है। हाईकोर्ट ने शासन को 20 सितंबर तक का समय देते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया है। अब 20 सितंबर को सुनवाई होगी।

मेरठ समेत विभिन्न शहरों में ई-रिक्शा के अवैध संचालन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार की ओर से सरकारी वकील ने कहा कि कुछ और समय दिया जाना चाहिए, ताकि अवैध ई-रिक्शा पर नियंत्रण के लिए गाइडलाइन तैयार की जा सके।

रूट तय करने के लिए समय की मांग की गई। कहा गया कि सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए गए हैं, इसलिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने उन्हें एक महीने का और समय दिया है। अब उन्हें 20 सितंबर को पूरे विवरण के साथ कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।

विदेश व्यापार घाटा कम करना जरूरी

डा. जयंती लाल भंडारी

हाल ही में 14 अगस्त को वाणिज्य विभाग के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विदेश व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार माह अप्रैल से जुलाई 2024 में 85.58 अरब डॉलर रहा है। पिछले वर्ष इसी समान अवधि में विदेश व्यापार घाटा 75.15 अरब डॉलर था।

यकीनन वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किया गया वर्ष 2024-25 का बजट उद्योगों को समृद्ध करने का भी बजट है। इस बजट के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करते हुए आयात घटाने व कृषि एवं वस्तु निर्यात बढ़ाने के अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश से निर्यात और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में खास ख्याल रखा गया है

हाल ही में 14 अगस्त को वाणिज्य विभाग के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विदेश व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार माह अप्रैल से जुलाई 2024 में 85.58 अरब डॉलर रहा है। पिछले वर्ष इसी समान अवधि में विदेश व्यापार घाटा 75.15 अरब डॉलर था। खासतौर से चीन से व्यापार घाटा और बढ़ा है। ऐसे में अब इस समय देश के समक्ष विदेश व्यापार के बढ़ते घाटे को कम करने और निर्यात बढ़ाने की नई जरूरत दिखाई दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इस वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि निर्यात बढ़ाने की रणनीतिक पहलों को उपयुक्त रूप से क्रियान्वित करके कृषि निर्यात बढ़ाने का कारगर प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इस वर्ष भारत से वस्तु एवं सेवा निर्यात बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछले दिनों बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट और अमरीका और जापान सहित दुनिया के कई देशों में मंदी के डर के परिदृश्य के बाद भारत के विदेश व्यापार घाटे की नई चुनौतियां उभर कर दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और पिछले वर्ष 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को 11 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि इस वित्त वर्ष में भारत के द्वारा कुल निर्यात का लक्ष्य पिछले वर्ष से भी कुछ अधिक 800 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाने का सुनिश्चित किया गया है, ऐसे में रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, लाल सागर संकट और कंटेनर की कमी की वजह से निर्यात के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ आयात में उपयुक्त रूप से कमी करके विदेश व्यापार घाटे को कम किया जाना होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की गठबंधन सरकार के द्वारा रणनीतिक रूप से विदेश व्यापार के बढ़ते घाटे को नियंत्रित करने और निर्यात की रफ्तार बढ़ाने के मद्देनजर मिशन मोड़ पर आगे बढ़ा जाना होगा।

इसके लिए पांच तरह के बहुआयामी उपाय सुनिश्चित किए जाने होंगे। एक, भारत के विदेश व्यापार में नई जान फूंकने के लिए द्विपक्षीय वार्ताएं बढ़ाई जाएं। दो, वर्ष 2024-25 के बजट के तहत निर्यात बढ़ाने के लिए सुनिश्चित किए गए अभूतपूर्व बजट आवंटनों का शुरुआत से ही कारगर उपयोग किया जाए। तीन, सेवा निर्यात को हर संभव तरीके से बढ़ाया जाए। चार, निर्यातकों को शुल्क के अलावा आने वाली बाधाओं (नॉन टैरिफ बैरियर) से राहत दी जाए और पांच, नए संभावित निर्यात बाजार तलाशे जाएं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि यकीनन इस समय नई गठबंधन सरकार वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों 11 जुलाई को नई दिल्ली में बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित देशों का संगठन) में भारत ने नई जान फूंकने की कोशिश की। भारत के द्वारा लगातार द्विपक्षीय व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने की पहल नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट तथा सागर नीति के तहत विदेश व्यापार बढ़ाने की पहल की जा रही है। इसी तरह भारत ने रूस सहित मित्र देशों और विभिन्न विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं से कारोबार बढ़ाने की नई कवायद शुरू की है। इसी परिप्रेक्ष्य में 8 से 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया के तीन दिवसीय दौरे के दौरान रूस और ऑस्ट्रिया के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं से विदेश व्यापार की नई संभावनाएं आगे बढ़ाई हैं।

यकीनन वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किया गया वर्ष 2024-25 का बजट उद्योगों को समृद्ध करने का भी बजट है। इस बजट के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करते हुए आयात घटाने व कृषि एवं वस्तु निर्यात बढ़ाने के अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश से निर्यात और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। वित्तमंत्री ने बजट में देश के 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। केंद्र, राज्य और निजी सेक्टर की आपसी सहभागिता से प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। उद्यमी को ऐसे औद्योगिक पार्क में जाकर सिर्फ उत्पादन शुरू करना होता है। नए बजट के प्रावधानों के तहत 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले सुविधा वाले औद्योगिक क्लस्टर या पार्क के विकसित होने से कम से कम 100 प्रकार के आइटम का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। वर्ष 2024-25 के बजट में वित्तमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर सशक्त बनाया है। निस्संदेह सरकार को ध्यान देना होगा कि कल तक पूरी दुनिया में भारत का सेवा निर्यात तेज रफ्तार से बढ़ रहे चमकीले सेक्टर के रूप में रेखांकित होता रहा है, लेकिन अब भारत के इसी प्रभावी सेवा निर्यात की रफ्तार सुस्त हो गई है। ऐसे में सेवा निर्यात की रफ्तार बढ़ाना जरूरी है। सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन से सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। यह जरूरी है कि निर्यातकों के समक्ष शुल्क के अलावा जो नॉन टैरिफ बाधाएं हैं, उन्हें दूर किया जाए। अभी तक करीब 200 नॉन टैरिफ बाधाएं चिन्हित की गई हैं। ये ऐसी बाधाएं हैं जो कई देश अपने आर्थिक लक्ष्यों और विदेश व्यापार को ध्यान में रखकर निर्मित करते हैं। ये सामान्यतया अनुचित और आयातकों से भेदभावकारी होती हैं। खासतौर से इनमें दस्तावेज से संबंधित प्रक्रियाएं, मौसमी शुल्क, टैरिफ कोटा, वस्तुओं की जांच और प्रमाणन, गुणवत्ता, आयात संबंधी पाबंदियां आदि शामिल हैं। ये बाधाएं मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद, फार्मास्युटिकल्स, खनिज पदार्थ आदि से संबंधित है। पिछले कई वर्षों से ऐसी बाधाओं से चीन, रूस सहित कई देशों की सरकारों को अवगत कराया गया है।

आम तौर पर नॉन टैरिफ बैरियर दूर करने में कई साल लग जाते हैं। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि सरकार के द्वारा अतिशीघ्र नॉन टैरिफ बैरियर से संबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाना लाभप्रद होगा, जिस पर सभी निर्यातक नॉन टैरिफ बैरियर की शिकायत दर्ज करा सकें, निर्यातकों के समक्ष विभिन्न देशों में आने वाली चुनौतियों का पता लगाया जा सके। साथ ही यदि ऐसे भी नियम विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नहीं हो तो सरकार के हस्तक्षेप से निर्यातकों को इससे जूझने से बचाने के उपाय किए जा सके। एक महत्त्वपूर्ण कदम यह भी उठाया जा सकता है कि चीन से गैर शुल्क बाधाएं समाप्त कराए जाने हेतु यूरोपीय देशों की तरह भारत के द्वारा भी चीन पर दबाव की रणनीति के तहत चीनी आयातों पर असाधारण आयात प्रतिबंध लगाने की रणनीति अपनाई जाए। पिछले माह 12 जून को यूरोपीय आयोग ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 48 फीसदी तक आयात शुल्क लगाना सुनिश्चित किया है। पिछले कई वर्षों से यूरोपीय देश चीन से आयात पर शुल्क की दरें 10 फीसदी तक ही सीमित किए हुए थे। हम उम्मीद करें कि इन विभिन्न रणनीतिक पहलों के उपयुक्त क्रियान्वयन से निर्यात बढने और आयात घटने का जो परिदृश्य निर्मित होते हुए दिखाई देगा, उससे देश के विदेश व्यापार घाटे में कमी आते हुए दिखाई दे सकेगी।

ज्ञान

बैंकों को प्रतिकूल रुझानों का सामना करना पड़ रहा

19 जुलाई को, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक जमा जुटाने और ऋण वृद्धि के बीच बढ़ते अंतर को चिह्नित किया, यह चिंता उन्होंने 8 अगस्त के आर.बी.आई .के मौद्रिक नीति निर्णय के बाद दोहराई। 28 जून तक, बैंक जमा में साल-दर-साल 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि ऋण वृद्धि 17.4 प्रतिशत थी। भारतीय बचत पैटर्न में बदलाव को स्वीकार करते हुए, उन्होंने बैंकों से जमा राशि जुटाने के प्रयास बढ़ाने का आह्वान किया। इसी तरह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में छोटी बचत जुटाने के आंकड़े पेश करते हुए देश की जमा वृद्धि दर में गिरावट पर प्रकाश डाला।

हाल के वर्षों में लोगों के दृष्टिकोण और उनकी बातचीत में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। कोविड के दौरान अलगाव गहन डिजिटलीकरण के साथ चला गया। भले ही डिजिटल विभाजन खत्म हो रहा है, प्रौद्योगिकी ने कई सेवाओं को बड़ी संख्या में सुलभ बना दिया है। इनमें निवेश और ऋण के सुविधाजनक रास्ते शामिल हैं। वित्तीय साक्षरता का प्रसार. विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, इसका नेतृत्व किया गया है। ढेर सारे निवेश विकल्पों में से जानकारीपूर्ण विकल्प चुने जा रहे हैं। महामारी के कारण घटती ब्याज दर व्यवस्था के कारण बैंक बचत और हिस्सेदारी के बीच रिटर्न की दर में बड़ा अंतर पैदा हो गया। गैर-ऋण साधनों से बेहतर रिटर्न की लोकप्रिय खोज, विशेष रूप से वास्तविक रूप में, ने बैंकों के पास रखे जाने वाले धन से एक बदलाव को चिह्नित किया है। निवेशक आज वित्तीय मध्यस्थता के लिए भुगतान करने के लिए कम इच्छुक दिखते हैं। यह उन संस्थानों द्वारा किया जाता है जो उधारकर्ताओं को उधार देने के लिए बचत जुटाते हैं। यह व्यावहारिक परिवर्तन वित्तीय बाजारों में एक आदर्श बदलाव का कारण बन रहा है।

वित्तीय बाजार एक संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं जो बड़े पैमाने पर समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न उपकरणों के माध्यम से व्यापार को सक्षम बनाता है। जैसा कि मैंने हाल के एक व्याख्यान में कहा था, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और प्रौद्योगिकी की परस्पर निर्भरता विलय पैदा करती है और उभरती आर्थिक प्रवृत्तियां अक्सर मनमौजी हो जाती हैं। बचतकर्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन से मध्यस्थ संस्थानों के व्यवसाय मॉडल पर संरचनात्मक परिणाम होंगे।

पिछले 1, 5, 15 और 20 वर्षों में, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी-50 इंडैक्स ने क्रमशः 28.6 प्रतिशत, 17.6 प्रतिशत, 11.8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न दिया है। मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों पर रिटर्न अधिक रहा है। बैंकिंग उद्योगों ने अभी भी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि अब व्यक्तिगत कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन व्यक्तिगत निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं, व्यापक आर्थिक प्रगति और कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों में सुधार के साथ-साथ हिस्सेदारी और भौतिक संपत्तियों (मुख्य रूप से रियल एस्टेट) पर उच्च रिटर्न के अनुभव के कारण उत्साहित बने हुए हैं।

पिछले 2 दशकों में पूंजी बाजार के सक्रिय विनियमन और घोटाले, मुक्त शेयर बाजार में उछाल के रिकॉर्ड (1991 और 2001 में देखे गए बड़े पैमाने पर बाजार कदाचार के विपरीत) ने जनता में विश्वास पैदा करके इन प्रवृत्तियों को मजबूत किया है।

सुरक्षा के मामले में, व्यक्तिगत निवेशक भी डैरीवेटिव सैगमैंट में निवेश करके जोखिम प्रबंधन के गुर सीख रहे हैं। अधिकांश व्यक्तिगत प्रतिभागियों द्वारा किए गए नुकसान के बावजूद, दैनिक स्वैप में खगोलीय लेन-देन को बाजार जोखिमों को कम करने के तरीके सीखने में उनके निवेश के रूप में देखा जा सकता है। कई बैंक, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, जमा पर प्रति वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की पेशकश कर रहे हैं, जो 10-वर्षीय सरकारी-सुरक्षा उपज से 10 से 75 आधार अंक अधिक है। फिर भी, जमा को आकर्षित करना कठिन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बैंकों की लाभप्रदता कम हो रही है। कुछ समय पहले, कुछ उधारदाताओं को 4-4.5 प्रतिशत का शुद्ध ब्याज मार्जिन प्राप्त था। अब ऐसा नहीं है।

गांव और शहरों का नियोजित निर्माण आवश्यक

सत्यपाल वशिष्ठ

हिमाचल सरकार को आपदा प्रबंधन नियमों के तहत भवन निर्माण करवाना चाहिए। हिमाचल में सरकारी एवं निजी भवन भूकंपरोधी बनाए जाने चाहिए और पुराने सरकारी एवं निजी भवनों का आडिट कर उनकी खामियों को दुरस्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में शहरों एवं गांवों में अवैज्ञानिक तथा बेतरतीब निर्माण हो रहा है, जो भूकंप के समय भयावह स्थिति पैदा करता है तथा बचाव कार्यों में बहुत दिक्कत पैदा करता है'

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं वाला राज्य है। प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं कुछ वर्षों से लगातार घटित हो रही हैं। वर्ष 2023-2024 में बादल फटने की घटनाओं ने भयावह रूप धारण कर लिया है। बादल फटने की घटनाओं के लिए हिमालय क्षेत्रों में बढ़ती निर्माण गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और प्राकृतिक आपदा जिसका खतरा भी हमेशा मंडरा रहा होता है वह है भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, जिसे रोका नहीं जा सकता, परंतु इसके खतरे की पहचान करके, सुरक्षित संरचनाओं का निर्माण और सुरक्षा पर शिक्षा प्रदान करके इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है, जो बिना किसी चेतावनी के घटित होती है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, क्योंकि अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती हैं। राज्य में भूकंपों का लंबा इतिहास दर्ज है। हिमाचल प्रदेश में 7 जिले चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर बहुत अधिक क्षति जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं, जबकि 5 जिले शिमला, किन्नौर, लाहुल-स्पीति और सिरमौर उच्च क्षति वाले जोखिम क्षेत्र में आते हैं। हिमाचल प्रदेश मे वर्ष 2022 में छोटे और मध्यम किस्म के 53 भूकंप आए। साल 2023 में 10 से अधिक झटके महसूस किए गए। मंडी में 9 जुलाई 2024 को सुबह के समय 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। जिला कांगड़ा में भी लगातार थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद भूकंप के झटके आते रहते हैं, परंतु इनकी तीव्रता कम होती है। 4 अप्रैल 1905 की सुबह आए 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने कांगड़ा में 20,000 इंसानी जानें ली और एक लाख के करीब इमारतें तहस-नहस की। अगर पिछले 100 वर्षों का रिकार्ड देखें तो हिमाचल प्रदेश में 1300 वार भूकंप के झटके आए हैं। इनमें से 7 झटके जिनकी तीव्रता 6 से 6.9 के बीच थी। शेष की तीव्रता कम ही रही है। कई बार अफगानिस्तान में आए भूकंप से धर्मशाला, शिमला और दिल्ली के भवनों के हिलने पर यही कह सकते हैं कि हमारे भवन भूकंप की दृष्टि से बहुत कमजोर हैं। वर्ष 2011 में राज्य द्वारा गिने गए 25,75,947 ढांचों में से कोई भी भूकंप प्रतिरोधी नहीं था। हिमाचल प्रदेश में भवन भूकंप रोधी नहीं हैं। ये नरम मिट्टी एवं ढ़लान पर बने हैं।

अगर नरम मिट्टी एवं ढ़लान पर बहुमंजिले भवन बने हों तो भूकंप ज्यादा नुकसान करता है। धर्मशाला में अवैध और बेतरतीब निर्माण को लेकर 2018 मे कार्यवाहक मुख्य नयायाधीश संजय करोल ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि क्या सरकार सोई हुई है, जो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील धर्मशाला में ऐसे निर्माण को होने दे रही है। हाल ही में समाचार पत्र मे छपी एक रिपोर्ट के अनुसार नूरपुर म्यूनिसिपल कमेटी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जोरों पर है। कोई नक्शा पास नहीं करवाया जाता है। रेवेन्यू तथा स्थानीय निकाय अवैध निर्माण के लिए कोई नोटिस जारी नहीं करते। वर्तमान में सरकार की शर्तों के अनुसार बिना एनओसी के पानी और बिजली का कनेक्शन भी मिल जाता है। इस तरह का निर्माण आपदा के समय दूसरे भवनों के लिए खतरा होता है। पालमपुर में भी अवैध निर्माण तथा टीसीपी के नियमों के विरुद्ध निर्माण को अनुमति देने के आरोप में म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जूनियर इंजीनियर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन की स्थिति सभी स्थानीय निकायों में नूरपुर और पालमपुर जैसी ही है। कैग ने 2017 में हिमाचल सरकार को चेतावनी दी थी कि शिमला में कई भवन ढ़लान पर बने हैं। भूकंप आने पर ज्यादा नुकसान होगा। अक्तूबर 2021 में शिमला कच्चीघाटी में कच्ची मिट्टी और ढ़लान पर बनी सात मंजिला भवन के गिरने से और साथ लगते भवनों को भी नुकसान हुआ। जुलाई 2019 में सोलन कुमारहट्टी मे धराशायी हुए चार मंजिल होटल में असम राईफल के कुछ सैनिक तथा होटल मालिक की मौत हो गई थी। हिमाचल सरकार को आपदा प्रबंधन नियमों के तहत भवन निर्माण करवाना चाहिए। हिमाचल में सरकारी एवं निजी भवन भूकंपरोधी बनाए जाने चाहिए और पुराने सरकारी एवं निजी भवनों का आडिट कर उनकी खामियों को दुरस्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में शहरों एवं गांवों में अवैज्ञानिक तथा बेतरतीब निर्माण हो रहा है, जो भूकंप के समय भयावह स्थिति पैदा करता है तथा बचाव कार्यों में बहुत दिक्कत पैदा करता है। ऐसे निर्माण के लिए म्युनिसिपल कमेटियां, नगर निगम एवं ग्राम पंचायतें जिम्मेदार हैं।

इसलिए नियोजित निर्माण के लिए यह अति आवश्यक है कि सरकारी एवं निजी भवनों के नक्शे पास करना, निर्माण का निरीक्षण, टीसीपी के नियमों की अनुपालना, भवन निर्माण के लिए मृदा परीक्षण, संरचना स्थिरता, भूकंप रोधी तकनीकों की अनुपालना, ढ़लान कटिंग, भवनों के सैट बैक, बिजली एवं पानी के कनेक्शन के लिए एनओसी जारी करना, भूकंप रोधी संरचनाओं को बनाने के लिए इंजीनियरों तथा मिस्त्रीयों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने आदि के कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से ही होने चाहिए। यह एक तकनीकी विभाग है तथा टीसीपी के नियमों से परिचित होता है। इसके लिए टीसीपी विभाग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। टीसीपी विभाग के निष्पक्ष कार्य के लिए किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गैरकानूनी तरीके से हो रहे निर्माण को समय पर रोकने के लिए पुलिस बल तथा कानूनी शक्तियां भी विभाग को मिलनी चाहिए ताकि समय रहते अवैध निर्माण को रोका जा सके। संपूर्ण राज्य के शहरों एवं गांवों मे 3-4 मंजिल तक भवन बनाने की ही अनुमति होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में किफायती भूकंपरोधी भवन बनाने को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भूकंप के समय नुकसान कम हो। समाचार पत्रों के माध्यम से विद्वान समय-समय पर आने वाली विभिन्न आपदाओं के बारे में जनता तथा प्रशासन को आगाह करते हैं तथा संबंधित सुझाव भी देते हैं। परंतु सरकार और जनता पर इन सुझावों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपदा अपना उग्र रूप बतलाती है तो कुछ समय के लिए मंथन होता है उसके बाद प्रशासन और जनता उस त्रासदी को फिर भूल जाती है।

राज्यत्व के बिन जनादेश

जम्मू-कश्मीर में सितंबर माह तक चुनाव कराए ही जाने थे, क्योंकि सर्वोच्च अदालत का आदेश था। जनादेश का यह समय 10 लंबे सालों के बाद आ रहा है, लेकिन कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। संसद 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त कर चुकी है, लिहाजा जम्मू-कश्मीर का 'विशेष दर्जा' समाप्त हो चुका है। अब यह भी देश के अन्य राज्यों और संघशासित क्षेत्रों सरीखा सामान्य क्षेत्र है। पुराना राज्य दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, लिहाजा राज्यत्व भी एक प्रमुख मुद्दा है। अब एक तरफ जम्मू-कश्मीर संघशासित क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ लद्दाख अलग होकर केंद्रशासित क्षेत्र है। अब सितंबर-अक्तूबर में जो विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, वे इन ऐतिहासिक बदलावों के संदर्भ में होंगे। यह भी गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। अब कश्मीर घाटी की 47 और जम्मू संभाग की 43, अर्थात कुल 90 सीटों पर, लोग जनादेश देंगे। सुखद है कि आतंक से छिले और घिरे एक इलाके में जम्हूरियत फिर लौट रही है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी और वे विधानसभा का स्वरूप तय करेंगे। ये चुनाव ऐसे परिदृश्य में हो रहे हैं, जब आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जो गिनती भर आतंकी सक्रिय लगते हैं, वे पाकपरस्त घुसपैठिए हैं। उनके खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। वैसे 2024 में ही जम्मू-कश्मीर में 36 आतंकी हमले किए जा चुके हैं।

उनमें 35 आतंकी मारे गए और 19 जवान 'शहीद' हुए, जबकि कुछ नागरिक भी मारे गए। ये आंकड़े 2014 के चुनावों से पहले के आतंकवादी माहौल की तुलना में बेहद कम हैं। उस दौर में 5 से 15 फीसदी तक ही मतदान हो पाता था। अब जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान 55-58 फीसदी तक मतदान किया गया और दशकों के रिकॉर्ड भी टूटे। बहरहाल आतंकी या उनके समर्थक अलगाववादी तत्त्व या तो जेल में बंद हैं अथवा बचे-खुचे चेहरे अपने घरों के भीतर चुपचाप बैठे हैं, लिहाजा यह दौर जनादेश के लिए बिलकुल सटीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के 'राज्यत्व' बहाली पर भी सरकार को स्पष्ट संकेत देने चाहिए थे। राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और राज्यत्व की बहाली तक चुनाव न लडने के ऐलान किए हैं। इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 और 35-ए को संसद ने निरस्त किया है और सर्वोच्च अदालत ने भी उसे 'उचित फैसला' करार दिया था। इसके बावजूद कांग्रेस यह दावा लगातार करती रही है कि अनुच्छेद 370 अब भी बरकरार है, उसे समाप्त नहीं किया गया। अच्छा यह होगा कि कांग्रेस ही किसी संवैधानिक मंच पर यह स्पष्ट करे कि किन आधारों पर पार्टी ऐसा दुष्प्रचार कर रही है। बहरहाल यह जनादेश का समय इसलिए भी है कि वहां हालात बदल चुके हैं। जिन होटलों के कमरे खाली रहते थे, वे अब लगभग बुक रहते हैं। सभी सार्वजनिक और सामाजिक संस्थान खुल चुके हैं। अब श्रीनगर के 'लाल चौक' पर लोग, 'तिरंगा' लहराते हुए, चुनावों की घोषणा के जश्न मना रहे हैं। बंद या बहिष्कार की कोई हुंकार नहीं है। पत्थरबाजी लगभग बीता अध्याय हो गई है। हज़ारों करोड़ रुपए के निवेश आ रहे हैं। कश्मीरी धंधे और हुनर फिर चमक उठे हैं। यानी बदला हुआ कश्मीर है। इस बदलाव के बावजूद आतंकवाद, बेरोजगारी, सुरक्षा, अनुच्छेद 370, राज्यत्व आदि प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे। जनादेश भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कान्फ्रेरेस, पीडीपी आदि किन दलों के पक्ष में रहेगा, अभी नहीं कहा जा सकता। 'इंडिया' नामक विपक्षी गठबंधन का कश्मीर में कोई अस्तित्व नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस और पीडीपी के हिस्से 'शून्य' आए थे।

अब्दुल्ला और भाजपा के बीच कांटेदार मुकाबला होना चाहिए। कुछ स्थानीय दलों और चेहरों ने भी चुनावी तौर पर चौंकाया है। तिहाड़ जेल में बंद, आतंकवाद समर्थक, इंजीनियर रशीद ने बारामूला संसदीय सीट पर उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोट से पराजित कर दिया था। इसी तरह महबूबा भी लोकसभा चुनाव हार गईं। तभी से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री सदमे की स्थिति में हैं। क्या ऐसे चौंकाने वाले जनादेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखेंगे? बहरहाल चुनाव के जोखिमों को भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। हमारे जांबाज जवान और खुफिया तंत्र जनादेश के इस पर्व को उल्लास से मनाने की स्थितियां बनाए रखेंगे, ऐसी देश को उम्मीद है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह चुनाव जम्मू-कश्मीर में किस तरह का बदलाव लाएंगे। चुनाव को लेकर हर किसी में उत्सुकता है।

इथेनॉल उत्पादन के लिए बढ़ाना होगा गन्ने का इस्तेमाल, क्या किसानों को मिलेगा फायदा?

परिवहन विशेष न्यूज

क्रिसिल रेटिंग्स का कहना है कि 2025 तक पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक गन्ने का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। इससे इथेनॉल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही साथ ही मिल मालिकों को भी काफी फायदा होगा जो वित्तीय मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इससे चीनी मिलों के कैश फ्लो में भी सुधार होगा। इसका फायदा गन्ना किसानों को भी हो सकता है।

नई दिल्ली। सरकार पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए जोरशोर से प्रयास कर रही है। इसके लिए 2030 तक लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन सरकार इसे 2025-26 तक ही हासिल कर लेना चाहती है। उसका मकसद क्रूड ऑयल के आयात पर निर्भरता घटाना है, जिसमें इथेनॉल मिश्रण काफी मदद करेगा। इससे सरकारी खजाने का काफी बोझ कम होगा, क्योंकि भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है।

लेकिन, क्रिसिल रेटिंग्स का कहना है कि 2025 तक पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक गन्ने का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। इससे इथेनॉल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, साथ ही मिल मालिकों को भी काफी फायदा होगा, जो वित्तीय मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इससे चीनी मिलों के कैश फ्लो में भी सुधार होगा, क्योंकि उन्हें सीधे पेट्रोलियम कंपनियों से इथेनॉल सप्लाई का पैसा मिलेगा। इसका फायदा गन्ना किसानों को भी मिल सकता है।

क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक, अगर सरकार को इथेनॉल सप्लाई ईयर (ESY) 2025 तक पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने या फिर सालाना 990 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है, तो अनाज और गन्ने दोनों के फीडस्टॉक के प्रभावी उपयोग की जरूरत होगी। अगले सीजन तक अनाज से सालाना इथेनॉल उत्पादन बढ़कर 600 करोड़ लीटर होने की उम्मीद है। इस सीजन में उत्पादन अनुमान 380 करोड़ लीटर है। बाकी इथेनॉल का उत्पादन गन्ने के जरिए होगा।

क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की अनियमित बारिश का गन्ना उत्पादन पर असर पड़ सकता है। ऐसे में मौजूदा सीजन में गन्ने से इथेनॉल प्रोडक्शन 250 करोड़ लीटर तक सीमित रहने की उम्मीद है। फिलहाल चीनी का उत्पादन सरकार के लिए चिंता का कोई विषय नहीं। इसलिए इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का अधिक इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। बाकी इथेनॉल के बड़े हिस्से का उत्पादन अनाज के जरिए किया जाएगा।

बैंक डिपॉजिट पर मिल सकता है ज्यादा ब्याज, वित्त मंत्री ने कहा- जमा योजनाओं को आकर्षक करें बैंक

परिवहन विशेष न्यूज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मीटिंग की। इसमें उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बैंकों को ब्याज दर के मामले में स्वतंत्रता दी है और इस आजादी का इस्तेमाल करके उन्हें जमा को अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कर्ज और जमा के बीच बढ़ते असंतुलन पर चिंता जताई थी।।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों से जमा वृद्धि में सुधार लाने को कहा। पिछले कुछ महीनों में ऋण वृद्धि जमा वृद्धि की तुलना में 3-4 प्रतिशत कम रही है, जिससे बैंकों के लिए परिसंपत्ति-देयता का असंतुलन पैदा हो गया है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री ने बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन के साथ ही पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर और पीएम विश्वकर्मा योजना सहित सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।

कर्ज-जमा का लगातार बिगड़ रहा संतुलन

वित्त मंत्री ने बैंकों के प्रमुखों से मुख्य बैंकिंग कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने और नवोन्मेषी उत्पादों को पेश करके जमा वृद्धि की गति बढ़ाने को कहा। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि जमा और कर्ज वृद्धि के बीच असंतुलन है। उन्होंने कहा, 'कर्ज देने में वृद्धि अधिक है और मैं विभिन्न कारणों से 19 अगस्त को बैंकों के प्रमुखों से मिलूंगी और उनसे जमा संग्रह के महत्व के बारे में बात करूंगी।' बजट 2024-25 पेश होने के बाद यह पहली समीक्षा बैठक थी। सरकारी बैंकों का शुद्ध लाभ मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो इससे पिछले साल की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है।

ब्याज दर पर आजादी का लाभ उठाएं बैंक

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आरबीआई ने बैंकों को ब्याज दर के मामले में स्वतंत्रता दी है और इस आजादी का इस्तेमाल करके उन्हें जमा को अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान साइबर सुरक्षा और वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों से संबंधित चिंताओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी और जानबूझकर चूक करने वालों से संबंधित मुद्दे और राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

6 दिन से निवेशकों को मालामाल कर रहा ओला इलेक्ट्रिक, आज भी लगा अपर सर्किट

परिवहन विशेष न्यूज

भाविश अग्रवाल के मालिकाना हक वाली ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ इसी महीने की शुरुआत में था। यह देश में किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी का पहला आईपीओ था। यह 9 अगस्त को शेयर मार्केट में 76 रुपये पर लिस्ट हुआ यानी आईपीओ में पैसा लगाने वालों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला। लेकिन यहां से ओला ने जो टॉप गियर लगाया वो रुकने का नाम नहीं ले रहा।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला था। आईपीओ की लिस्टिंग भी फ्लैट हुई थी। लेकिन, उसके बाद शेयरों ने टॉप गियर लगाया और 6 दिन के भीतर निवेशकों का पैसा तकरीबन दोगुना कर दिया। शेयर मार्केट के कई जानकार ओला इलेक्ट्रिक के फंडामेंटल्स को कमजोर बताकर निवेश से बचने की सलाह दे रहे थे। फिर भी ओला के शेयरों में जबरदस्त तेजी दिखने को मिल रही है। सोमवार को भी इसमें करीब 10 फीसदी का उछाल दिखा।

कब आया था ओला का आईपीओ

अरबपति कारोबारी भाविश अग्रवाल के मालिकाना हक वाली ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ इसी महीने की शुरुआत में था। यह देश में किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी का पहला आईपीओ था। यह 9 अगस्त को शेयर मार्केट में 76 रुपये की अपर प्राइस बैंड पर लिस्ट हुआ यानी आईपीओ में पैसा लगाने वालों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला। लेकिन, यहां से ओला ने जो टॉप गियर लगाया, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा।

ओला ने अब तक कितना रिटर्न दिया?

ओला की लिस्टिंग के बाद से शेयर मार्केट में सिर्फ 6 दिन कारोबार हुआ है। लेकिन, इन 6 ही दिनों में निवेशकों का पैसा तकरीबन डबल हो गया। सोमवार को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 10 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 146.38 रुपये पर बंद हुए। ओला इलेक्ट्रिक के मालिक भाविश अग्रवाल ने हाल में ही रोडस्टर, रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो नाम से इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है और कंपनी को लेकर अपने आगे के प्लान के बारे में भी बात की है। इससे भी निवेशकों का हौसला बढ़ा है।

कैसा रहा था ओला का तिमाही नतीजा?

ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले दिनों वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही का नतीजा जारी किया था। जून तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 32 फीसदी बढ़ा है। हालांकि, इसी के साथ कंपनी के घाटे में इजाफा हुआ। ओला इलेक्ट्रिक को पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 267 का घाटा हुआ था, जो इस साल बढ़कर 347 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, निवेशक कंपनी की आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखकर पैसा लगा रहे हैं।

स्टॉक मार्केट में सुस्ती के बीच 5 शेयरों में दिखी तूफानी तेजी, मालामाल हुए निवेशक

सप्ताह का पहला कारोबारी दिन सुस्त रहा। सेंसेक्स और निफ्टी की फ्लैट बंद हुए। मेटल तेल-गैस एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। IT और फार्मा इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि ऑटो और बैंकिंग शेयरों में पर दबाव दिखा। इस सुस्ती भरे माहौल में भी कुछ शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। आइए इन शेयरों को बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। इस हफ्ते का पहला दिन काफी सुस्त रहा। रक्षाबंधन के दिन दोनों प्रमुख सूचकांक यानी सेंसेक्स और निफ्टी लगभग फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स में जहां मामूली गिरावट आई, वहीं निफ्टी में मामूली बढ़त दिखी। हालांकि, शेयर मार्केट में ओवरऑल सुस्ती के बीच भी कुछ शेयरों में जबरदस्त तेजी दिखी और निवेशकों को अच्छा मुनाफा हुआ।

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड

तंबाकू, पान मसाला से लेकर चाय तक कारोबार करने वाली गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी दिखी। मोदी एंटरप्राइजेज का हिस्सा गॉडफ्रे फिलिप्स सोमवार को 16.27 फीसदी उछाल के साथ 5270.65 रुपये पर बंद हुआ।

कैपलिन प्वाइंट लैबोरेट्रीज

कैपलिन प्वाइंट प्रयोगशालाएँ सोमवार को 15.45 फीसदी उछाल के साथ 1,830.40 रुपये पर बंद हुआ। दरअसल, ब्राजील की हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी-ANVISA ने कंपनी के एक प्लांट का निरीक्षण पूरा कर लिया है। इसमें स्टेराइल्स इंजेक्टेबल और आंखों से जुड़ी दवाएं बनती हैं।

रेगुलेटरी एजेंसी ने कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की, जिससे निवेशकों का मनोबल बढ़ा और इसका असर शेयरों पर दिखा।

IIFL फाइनेंस लिमिटेड

IIFL Finance के शेयरों में सोमवार को 12.29 फीसदी की तेजी दिखी और यह 455.30 रुपये पर बंद हुआ। यह फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी पिछले कुछ समय से रेगुलेटरी नियमों से जूझ रही थी। आरबीआई ने इस पर कुछ बंदिशें भी लगाई थी और कंपनी के तिमाही नतीजे भी कमजोर आए थे। हालांकि, अब कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

फूड एंड इन्स लिमिटेड

Foods And Inns Ltd फलों के गूदे और सूखे फलों के साथ मसालों के कारोबार से जुड़ी है। यह वेजिटेबल पाउडर भी बनाती है। कंपनी के तिमाही नतीजे कमजोर रहे थे, जिसके चलते इसके शेयरों में कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन, सोमवार को फूड एंड इन्स के शेयर 10.60 फीसदी उछाल के साथ 143.70 रुपये पर बंद हुए।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

Ola Electric Mobility के शेयर में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। कंपनी के शेयर सोमवार को 10 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 146.4 रुपये पर बंद हुए। ओला की हाल ही में शेयर मार्केट में लगभग फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। लेकिन, उसके बाद से ओला के पैर एक्सीलेटर से नहीं हटे हैं। इसने 6 कारोबारी दिनों निवेशकों का पैसा तकरीबन दोगुना कर दिया है।

हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में क्यों थम नहीं रही गिरावट, कहां तक आ सकता है भाव?

अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए हिंदुस्तान जिंक में अपनी 3.17 फीसदी हिस्सेदारी बेच रहा है। OFS में स्टॉक की कीमत 486 रुपये है। यही वजह है कि हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है और अब बाजार भी OFS वाली कीमत के आसपास आ गया है। आइए जानते हैं कि वेदांता ग्रुप अपनी सब्सिडियरी कंपनी में हिस्सेदारी क्यों बेच रहा है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc Shares) के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अनिल अग्रवाल के मालिकाना हक वाली इस कंपनी का शेयर मई में 808 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन, उसके बाद से इसमें लगातार करेक्शन देखने को मिला। चार दिन में इसका भाव करीब 20 फीसदी तक गिर चुका है। सोमवार को भी इसके शेयरों में 4 फीसदी से अधिक गिरावट आई और इसका भाव मई के बाद पहली बार 500 रुपये के नीचे आया।

क्या है गिरावट की वजह?

दरअसल, हिंदुस्तान जिंक की प्रमोटर वेदांता (Vedanta) ने ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का एलान किया। तभी से हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। अब यह 486 रुपये के अपने ऑफर फॉर सेल के फ्लोर प्राइस के करीब आ गया है। रिटेल निवेशकों के लिए वेदांता का OFS सोमवार (19 अगस्त) को खुला। वहीं, बाकी निवेशकों के लिए यह 16 अगस्त से खुला है।

जून तिमाही के अंत तक वेदांता लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक में 64.92 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं, भारत सरकार के पास 29.54 फीसदी स्टेक था। बाकी हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थी।

दिवाली के लिए महंगा हुआ हवाई सफर, किराए में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि

परिवहन विशेष न्यूज

एक विश्लेषण से पता चलता है कि 30 अक्टूबर से पांच नवंबर के दौरान दिल्ली-चेन्नई मार्ग पर सीधी उड़ान के लिए इकोनमी श्रेणी का औसत एकतरफा किराया 25 प्रतिशत बढ़कर 7618 रुपये है। यह किराया पिछले साल 10-16 नवंबर के मुकाबले है। इसी अवधि में मुंबई-हैदराबाद मार्ग पर टिकट की कीमत 21 प्रतिशत बढ़कर 5162 रुपये हो गई है। दिल्ली-गोवा तथा दिल्ली-अहमदाबाद मार्गों पर भी किराया बढ़ा है।

नई दिल्ली। आगामी त्योहारी सत्र के लिए हवाई यात्रा के किराए में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और दिवाली के लिए प्रमुख घरेलू मार्गों पर औसत एकतरफा टिकट की कीमत 10-15 प्रतिशत बढ़ चुकी है। दूसरी ओर ओणम के दौरान केरल के शहरों के लिए कुछ उड़ानों का किराया 20-25 प्रतिशत अधिक है।

ट्रैवल पोर्टल इक्सिगो के एक विश्लेषण से पता चलता है कि 30 अक्टूबर से पांच नवंबर के दौरान दिल्ली-चेन्नई मार्ग पर सीधी उड़ान के लिए इकोनमी श्रेणी का औसत एकतरफा किराया 25 प्रतिशत बढ़कर 7,618 रुपये है। यह किराया पिछले साल 10-16 नवंबर के मुकाबले है। इसी अवधि में मुंबई-हैदराबाद मार्ग पर टिकट की कीमत 21 प्रतिशत बढ़कर 5,162 रुपये हो गई है। दिल्ली-गोवा तथा दिल्ली-अहमदाबाद मार्गों पर किराया 19 प्रतिशत बढ़कर 5,999 रुपये तथा 4,930 रुपये हो गया है।

भारत में हवाई यात्रियों की संख्या

एक अनुमान के मुताबिक, भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात साल 2030 तक 30 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह साल 2023 के मुकाबले तकरीबन दोगुना होगा, जब 15 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी थी। विमानन कंपनियां अपनी कैपेसिटी में भी लगातार विस्तार कर रही हैं, ताकि वे बढ़ती डिमांड को पूरा कर सकें। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि आने वाले समय में हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, प्रतिस्पर्धा और लागत के बढ़ने की वजह से मुनाफे में वृद्धि की रफ्तार धीमी रह सकती है।

सेबी को होगा 76,293 करोड़ का नुकसान? मार्केट रेगुलेटर ने कहा- मुश्किल है बकाया रकम की वसूली

सेबी ने 76293 करोड़ रुपये को डिफिकल्ट टु रिकवर (DTR) कैटेगरी में रखा है। DTR वह बकाया रकम होती हैं जिन्हें सभी प्रयासों के बाद भी वसूल नहीं किया जा सका। सेबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2023-24 में कहा है कि ऐसी DTR बकाया राशि की अलग-अलग कैटेगरी में बांटना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और यह वसूली अधिकारियों को DTR की वसूली से नहीं रोकता है।

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 76,293 करोड़ रुपये बकाया राशि की वसूली को 'मुश्किल' की श्रेणी में रखा है। यह रकम पिछले साल की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा अदालत के आदेश से नियुक्त समितियों के समक्ष लंबित मामलों के कारण है। बकाया राशि की वसूली कठिन है। यह ऐसी राशि है, जिनकी वसूली पुनरोद्धार के सभी उपायों को लागू करने के बाद भी नहीं हो पाई है।

सेबी ने 2023 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा, 'डिफिकल्ट टु रिकवर (डीटीआर) यानी वसूली में मुश्किल बकाया को अलग करना पूरी तरह से एक प्रशासनिक कार्य है। यह अधिकारियों को डीटीआर के रूप में अलग की गई राशि की वसूलने से नहीं रोकेगा।'

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक सेबी ने डीटीआर के रूप में 807 मामलों की पहचान की। इन पर कुल बकाया 76,293 करोड़ रुपये था। वहीं पिछले साल 73,287 करोड़ रुपये के 692 मामले थे। इन 807 मामलों में से 36 मामले राज्य की अदालतों, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चल रही कार्यवाही के कारण लंबित हैं।

इन मामलों में 12,199 करोड़ रुपये की राशि शामिल हैं। इसके अलावा, 60 मामले अदालत द्वारा गठित समितियों के समक्ष हैं, जिनमें 59,970 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन दोनों श्रेणियों में अभी तक वसूल की जाने वाली कुल राशि का 95 प्रतिशत हिस्सा है। सेबी अपनी कार्यवाही की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सालाना रिपोर्ट के माध्यम से 2021-22 के बाद से बकाया राशि वसूली के मुश्किल मामलों को लेकर आंकड़े जारी कर रहा है।

कुल मिलाकर, सेबी के पास 1.03 लाख करोड़ रुपये की वसूली करने लायक बकाया राशि है। इसमें वे संस्थाएं शामिल हैं, जो जुर्माने का भुगतान नहीं कर पाईं या फिर जिनको सेबी की तरफ से निवेशकों की रकम रिफंड करने को आदेश मिला था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को निर्णय अधिकारी (adjudicating officer) द्वारा लगाए गए दंडों की वसूली का अधिकार है। सेबी ने 2023-24 के दौरान 342 नए मामलों की जांच शुरू की, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए 144 मामलों से कहीं अधिक है।

हवाई सफर करने वालों की बढ़ रही तादाद, एक महीने में 1.29 करोड़ लोगों ने पकड़ी फ्लाइट

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जुलाई में 1.29 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया। यह एक साल पहले के मुकाबले 7.3 फीसदी अधिक है। एक अनुमान के मुताबिक भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात साल 2030 तक 30 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह साल 2023 के मुकाबले तकरीबन दोगुना होगा जब 15 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी थी।

नई दिल्ली। भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने जुलाई में 1.29 करोड़ से अधिक यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाया। यह सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। हालांकि, जुलाई में हवाई यातायात इस साल जून की तुलना में कम था, जब 1.32 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी थी। इंडिगो ने घरेलू हवाई यातायात क्षेत्र पर अपना दबदबा जारी रखा और जुलाई में इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 62 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर एयर इंडिया की हिस्सेदारी घटकर 14.3 प्रतिशत रह गई।

अकासा एयर की हिस्सेदारी घटी

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने विस्तारा की घरेलू बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई। एआइएक्स कनेक्ट और स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत रह गई। इसके अलावा, अकासा एयर और अलायंस एयर की हिस्सेदारी क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत तक गिर गई।

डीजीसीए ने कहा, 'जनवरी-जुलाई, 2024 के दौरान घरेलू एयरलाइंस ने 923.35 लाख लोगों को यात्रा कराई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 881.94 लाख था। इस तरह यात्रियों की संख्या में 4.70 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और 7.33 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्ज की गई।'

मोदी सरकार गिराने की अमरीकी साजिश: रूस

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विश्व में चढते परवान और वैश्विक नेता के रूप में उभरने से कई विदेशी और देसी ताकतें मोदी की खिलाफत में शेकहैंड कर चुकी है।

अब बात सामने आई है कि मोदी सरकार को उखाड फेंकने के लिए अमेरिका की खुफिया ऐजेंसी CIA पर्दे के पीछे से बडे पैमाने पर प्रयास कर रही है। रूस के सरकारी मीडिया स्पूतनिक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि CIA ,आन्ध्रप्रदेश के बैपटिस्ट चर्च और विपक्षी नेताओ के संपर्क में है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार को उखाड गिराने की एक बडी साजिश रच रही है। बता दें कि रूस की स्पूतनिक मीडिया की इस रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है।इससे पहले बंगला देश सरकार को उखाड फेंकने का आरोप भी अमेरिका पर लग चुका है। अब स्पूतनिक ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा सरकार को गिराने की अमेरिकी साजिश का दावा किया है। रूसी मीडिया ने अमेरिकी राजदूत और कुछ अधिकारियों द्वारा बार-बार भारत के विपक्षी नेताओ के साथ बैठक करने पर चिंता व्यक्त की है। रूसी मीडिया स्पूतनिक के मुताबिक, जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।इसके लिए बडे पैमाने पर प्रयास किये जा रहे है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, जो विपक्षी नेताओ के साथ लगातार संपर्क में है। कुछ नेताओ से मुलाकात की है और

बातचीत की है। अमेरिकी महावाणिज्यदूत जेनिफर लार्सन ने हाल ही में हैदराबाद में AIMIM नेता असदुद्दीन औवेसी से मुलाकात की थी। इससे पहले वह आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू से भी मिली थी।इतना ही नहीं उन्होने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव से भी मुलाकात की थी। बता दें कि रूसी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी घटनाओ का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लार्सन हैदराबाद में अमेरिकी मिशन संस्था के जरिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA बैप्टिस्ट चर्च की मदद लेने की कोशिश कर रही है। रूस की स्पूतनिक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि CIA का पहला टार्गेट चन्द्रबाबू नायडू की मदद से उनका समर्थन वापस पाना है। बैप्टिस चर्च के जरिये नायडू को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर चन्द्रबाबू नायडू समर्थन वापसी में हिचकिचाते है तो विपक्ष को इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने का निर्देश दिया है। रूसी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी वाणिज्यिदूत और राजनयिको द्वारा विपक्षी नेताओ से मुलाकात चिंता का विषय है। रूसी मीडिया ने तो यहां तक कह डाला कि मोदी विरोधी। नेताओ, सामाजिक कार्यकर्ताओ, सोशल मीडिया हस्तियों उधोगपतियो और कलाकारो समेत कई लोगो को इस अभियान के लिए व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।रूसी मीडिया स्पूतनिक ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि जुलाई, 2024 में अमेरिकी दूतावास ने भारत में इन्फ्लूएंस टू इम्पैक्ट यानि प्रभाव डालने के लिए प्रभाव नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी,को आमंत्रित किया गया था। जो कांग्रेस के प्रचारको को बढावा देते है। और यूट्यूब के माध्यम से आधे सच फैलाकर मोदी सरकार के खिलाफ काम करते है। स्पूतनिक की रिपोर्ट में कहा है कि भारत में रहकर हिंदू त्यौहारो और देवी देवताओ के खिलाफ बोलने वाले और भारत विरोधी रूख रखने वाले आरजे सैयमा को अमेरीकी दूतावास ने समानता के राजदूत का खिताब देकर सम्मानित किया था। मीडिया का कहना है कि यह सब खेल भारत के लोगो को मोदी सरकार के खिलाफ भटकाने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है।

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून कैसे बनेगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दिया क्लियर

केंद्रीय कानून की मांग कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में 25 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी है। अधिकारियों ने कहा कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों द्वारा अपना सुरक्षा मूल्यांकन करने के बाद उनकी व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को मंजूरी दी जाएगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाने और इसके लिए अध्यादेश जारी करने की मांग को औचित्यहीन करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार स्वास्थ्य पूरी तरह से राज्यों का विषय है और 26 राज्यों ने अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बना रखा है। राज्य का विषय होने के कारण केंद्र राज्यों को सिर्फ एडवाइजरी भेज सकता है।

वहीं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मांग को मानते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 25 फीसद तक बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कई रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ सोमवार को हुई चर्चा भी बेनतीजा रही।

स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा

डॉक्टर एसोसिएशन स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाने और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने पर अड़े हुए हैं। शीर्ष अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर एसोसिएशन ने दो दिन पहले यह नई मांग जोड़ दी है, जिसे पूरा करना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है।

केंद्रीय कानून बनाने की मांग

उन्होंने कहा कि आरजी कर मेडिकल कालेज में हुई हृदयविदारक घटना को देखते हुए डॉक्टर एसोसिएशन की केंद्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोलकाता में हुई घटना इस तरह के किसी कानून से कवर नहीं हो सकता है। वह केवल भारतीय न्याय संहिता के तहत ही कवर हो सकता है, जिसके तहत कार्रवाई हो भी रही है।

कानून बनाने की मांग खारिज

शीर्ष अधिकारी के अनुसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक जुलाई को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने की मांग को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्यों में पर्याप्त कानून हैं और केवल उन्हें अमल में लाने की जरूरत है। राज्यों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कानून में गैर जमानती धाराएं जोड़ रखी हैं और कड़ी सजा भी प्रविधान कर रखा है।

मांगों को स्वीकार कर लिया गया

उन्होंने कहा कि इन कानूनों को अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी के अनुसार डॉक्टर एसोसिएशन की वाजिब मांगों को स्वीकार कर लिया गया है।

रक्षाकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी

उनकी मांग के अनुरूप केंद्र सरकार के मातहत आने वाले सभी अस्पतालों में तैनात सुरक्षाकर्मियों की संख्या में 25 फीसद तक की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है। इसके पहले देश के सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की स्थिति में छह घंटे के भीतर संस्थान की ओर एफआइआर दर्ज करने की एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है।

मंत्रालय ने रखी अपनी मांग

इसी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कमेटी बनाने को भी तैयार है, जिसमें डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। लेकिन कमेटी के गठन के पहले डॉक्टर एसोसिएशन को हड़ताल खत्म कर वापस काम पर जाना होगा और अचौत्यहीन मांगों को छोड़ना होगा।

डॉक्टर हत्या मामले में आरोपी का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, कोर्ट से CBI को मिली अनुमति

कोलकाता की एक अदालत ने सीबीआई को संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी।सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक आरोपित संजय राय का पालीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति कोर्ट से मिल गई है। टेस्ट कब होगा इस बारे में सीबीआई जल्द ही फैसला लेगी। कोलकाता के इस हत्याकांड के मामले में भी सीबीआई संजय राय से कुछ सवाल करेगी।

कोलकाता। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। कोलकाता की एक अदालत ने सीबीआई को संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी, जिन पर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप है। विशेष रूप से, संजय रॉय कोलकाता पुलिस से जुड़े एक नागरिक स्वयंसेवक हैं। टेस्ट कब होगा इस बारे में सीबीआई जल्द ही फैसला लेगी। इस टेस्ट के जरिए अपराधी झूठ बोल रहा है या सही इसका पता लगाया जाता है। सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दाखिल की थी। इस तरह के टेस्ट में सीबीआई के कुछ डाक्टरों की एक सीएफएसएल टीम जांच करती है। कोलकाता के इस हत्याकांड के मामले में भी सीबीआइ संजय राय से कुछ सवाल करेगी।

14 अगस्त से सीबीआई ने शुरू की जांच: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ट्रेनी महिला डाक्टर से दुष्कर्म किया गया और हत्या कर दी गई थी। महिला चिकित्सक का शव नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर मिला था। अपराध में कथित संलिप्तता के लिए अगले दिन कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई ने 14 अगस्त से अपनी जांच शुरू कर दी है।

क्या होता पॉलीग्राफ ? : पॉलीग्राफ यह एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। खास कर इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी अपराध का पता लगाना हो। पालीग्राफ टेस्ट को झूठ पकड़ने वाली मशीन अथवा लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है।

यादगार रहेगी इस साल की राखी, भाई ने तोहफे में दान की अपनी बहन को किडनी; गोवा का है मामला

परिवहन विशेष न्यूज

इस रक्षाबंधन दक्षिण गोवा के एक भाई ने अपनी बहन को तोहफे में किडनी दान की है। बता दें कि महिला पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित थी। महिला को अप्रैल में एक निजी अस्पताल में उसके 35 वर्षीय भाई से किडनी दान में मिली। महिला के पति ने कहा कि मेरी पत्नी अपने भाई को राखी बांधते समय भावुक हो गई थी।

नई दिल्ली। रक्षाबंधन का त्यौहार दक्षिण गोवा की 43 वर्षीय महिला के लिए बेहद खास रहा। दरअसल, इस साल की शुरुआत में उसके छोटे भाई ने अपनी बहन को अपनी एक किडनी दान करके नई जिंदगी दी।

पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित थी महिला

बता दें कि महिला पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित थी। महिला को अप्रैल में एक निजी अस्पताल में उसके 35 वर्षीय भाई से किडनी मिली थी। हालांकि, परिवार के अनुरोध पर भाई-बहन की जोड़ी के नाम गुप्त रखे गए हैं, लेकिन वे अंग दान करने वालों के लिए प्रेरणा बन गए हैं।

राखी बांधते समय भावुक हुई बहन

महिला के पति ने कहा, 'मेरी पत्नी अपने भाई को राखी बांधते समय भावुक हो गई थी। बचपन से ही वे आदर्श भाई-बहन रहे हैं। निजी अस्पताल के एक नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा कि महिला पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित थी और लास्ट स्टेज में थी, जिसके लिए तुरंत ट्रांसप्लांट करना जरूरी था।

मरीज का छोटा भाई भी अपनी किडनी दान करने के लिए तैयार था। डॉक्टर ने बताया कि पहले उसका किडनी स्टोन का इलाज किया गया और जरूरी अनुमति के बाद लेप्रोस्कोपिक किडनी डोनेशन विधि से अंग दान किया गया।

पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का चेन्नई में निधन, कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने में निभाई थी बड़ी भूमिका

पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का चेन्नई में निधन हो गया। 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। जनरल पद्मनाभन के परिवार में उनकी पत्नी बेटी और एक बेटा है। उनके बच्चे अमेरिका से लौट रहे हैं। जनरल पद्मनाभन का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम होगा। बता दें कि वह जुलाई 1993 से फरवरी 1995 तक कश्मीर घाटी में 15 कोर के कमांडर थे।

चेन्नई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का चेन्नई में निधन हो गया। वह 83 साल के थे। उनको सैन्य हलकों में प्यार से 'पैडी' के नाम से जाना जाता था। वह 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक थल सेनाध्यक्ष थे। जनरल पद्मनाभन के परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और एक बेटा है। उनके बच्चे अमेरिका से लौट रहे हैं। जनरल पद्मनाभन का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम होगा। दिल्ली में प्रतिष्ठित एनडीसी कोर्स में भाग लेने से पहले जनरल पद्मनाभन ने एक स्वतंत्र ब्रिगेड और एक माउंटेन ब्रिगेड की कमान संभाली थी। 15 कोर कमांडर के रूप में सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

1988 से फरवरी 1991 तक इन्फैंट्री ब्रिगेड की संभाली थी कमान

पांच दिसंबर 1940 को केरल के तिरुवंतपुरम में जन्मे जनरल पद्मनाभन प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे के पूर्व छात्र थे। जनरल पद्मनाभन ने 1988 से फरवरी 1991 तक रांची, बिहार और पंजाब में एक इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली थी।

कश्मीर घाटी में 15 कोर के कमांडर थे

लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नति के बाद वह जुलाई 1993 से फरवरी 1995 तक कश्मीर घाटी में 15 कोर के कमांडर थे। उनके कार्यकाल के दौरान सेना ने कश्मीर में आतंकियों पर बड़ी बढ़त हासिल की। वह 43 वर्ष से अधिक की प्रतिष्ठित सैन्य सेवा पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2002 को सेवानिवृत्त हुए थे।

भारत में तेजी से बढ़ रहा Mpox का खतरा, एयरपोर्ट और सीमा पर अलर्ट

अफ्रीका से चला खतरनाक एमपॉक्स वायरस पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच गया है। ऐसे में विश्व स्तर पर एमपॉक्स की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने बांग्लादेश और पाकिस्तान हवाई अड्डों बंदरगाहों और सीमाओं पर अधिकारियों को एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं अस्पतालों को मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने को कहा गया है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। खतरनाक एमपॉक्स यानी मंकीपॉक्स ने अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में दस्तक दे दी है। ऐसे में इसने भारत के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। इसके मद्देनजर केंद्र ने बांग्लादेश और पाकिस्तान हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमाओं पर अधिकारियों को आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लेकर सतर्क रहने को कहा है।

साथ ही सरकार ने अस्पतालों को मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने को कहा गया है। अब आपको हम 10 प्वाइंट में मंकीपॉक्स को लेकर की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

एमपॉक्स रोगियों का अलग से इलाज करने के लिए दिल्ली में तीन सरकारी अस्पतालों को प्रमुख सुविधाओं के रूप में चुना गया है। इन तीन अस्पतालों में राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल के नाम शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने जल्द पता लगाने के लिए बढ़ी निगरानी के बीच एमपॉक्स के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को एक बैठक की अध्यक्षता की।

केंद्र ने सभी राज्यों से एमपॉक्स मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रखने को कहा है। सूत्रों ने कहा कि इन अस्पतालों को नोडल केंद्र के रूप में नामित किया जाना चाहिए और इसकी जानकारी जनता को दी जानी चाहिए।

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल देश से एमपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आकलन के अनुसार, निरंतर संचरण के साथ इसके फैलना का खतरा कम है।

इस बार का वायरस स्ट्रेन अलग है और अधिक जहरीला और संक्रामक है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, लेकिन मौजूदा आकलन के अनुसार, देश में निरंतर प्रसारण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अफ्रीका के कई हिस्सों में इसकी व्यापकता और प्रसार को देखते हुए एमपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बीमारी के शीघ्र इलाज के लिए तैयार है। वर्तमान में, देश में 32 प्रयोगशालाएं एमपॉक्स परीक्षण के लिए रखी गई हैं।

डब्ल्यूएचओ के एक पूर्व बयान में कहा गया है कि 2022 से 116 देशों में एमपॉक्स के कारण 99,176 मामले और 208 मौतें हुई हैं।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एमपॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल, दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। इस साल, अब तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या पिछले साल की कुल संख्या से अधिक हो गई है, जिसमें 15,600 से अधिक मामले और 537 मौतें शामिल हैं।

2022 के बाद से भारत में कम से कम 30 एमपॉक्स के मामले सामने आए हैं। एमपॉक्स का आखिरी मामला इसी साल मार्च में सामने आया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023